सोशल मीडिया से जुड़ें

www.newsparivahan.com

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

परिवहन विशेष

वर्ष 04, अंक 207, नई दिल्ली, रविवार 01 नवम्बर 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र



02 प्रदूषण का प्रहार: गर्भस्थ शिशु का जीवन भी खतरे में

06 डॉक्टर बनने का सपना, लंबी ट्रेनिंग और पारिवारिक जीवन की अनदेखी

08 झारखंड के 28 पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री दक्षता मेडल

दिल्ली के 48 गांव अब ग्रामीण नहीं, शहरी घोषित - उपराज्यपाल ने जारी की ऐतिहासिक अधिसूचना

दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 507(क) के तहत बड़ा फैसला | 23 अक्टूबर 2026 की दिल्ली राजपत्र असाधारण में प्रकाशित

प्रस्तुतकर्ता:- परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक - प्रधान संपादक: संजय कुमार बाठला - सह संपादक: पिंकी कुंडू

मुख्य तथ्य / फैक्ट बॉक्स:
- राजपत्र संख्या: 323 / SG-DL-E-27102026-277440 | दिनांक: दिल्ली, शुक्रवार 23 अक्टूबर 2026 / कार्तिक 1, 1948

- जारीकर्ता: शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार | आदेश उपराज्यपाल महोदय के नाम पर - विशेष सचिव (शहरी विकास) मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा हस्ताक्षरित

- कानूनी आधार: दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 507 के खंड (क) के तहत प्राप्त शक्तियां

- प्रभाव: अनुसूची में उल्लिखित गांव अब ग्रामीण क्षेत्र नहीं माने जाएंगे, उनकी संपूर्ण राजस्व संपदा पुरानी आबादियों सहित शहरी क्षेत्र घोषित

विस्तृत विवरण और अनुसूची:

राजस्व क्षेत्र - बाहरी उत्तर (15 गांव):

1. बाकोली, 2. हमीदपुर, 3. पल्ला, 4. किवायाकपुर, 5. सिंघोला, 6. सुंगरपुर दिल्ली, 7. सुंगरपुर शाहदरा, 8. ताजपुर कलां, 9. तेहरी दौलतपुर, 10. राजपुर कलां, 11. औचांडी, 12. मुंगेपुर, 13. शाहपुरगढ़ी, 14. निजामपुर रसीदपुर, 15. चटेसर

राजस्व क्षेत्र - उत्तर (2 गांव):

16. पुर दिल्ली, 17. जगतपुर दिल्ली

राजस्व क्षेत्र - उत्तर पश्चिम (1 गांव):

18. सुल्तानपुर माजरा

राजस्व क्षेत्र - (पूर्वी दिल्ली क्षेत्र) (8 गांव):

19. पुर शाहदरा, 20. सबापुर दिल्ली, 21. बदरपुर खादर, 22. बाकियाबाद, 23. खानपुर खानी, 24. जाफराबाद, 25. जगतपुर शाहदरा, 26. बदरपुर माजरा बुराड़ी

राजस्व क्षेत्र - दक्षिण (2 गांव):

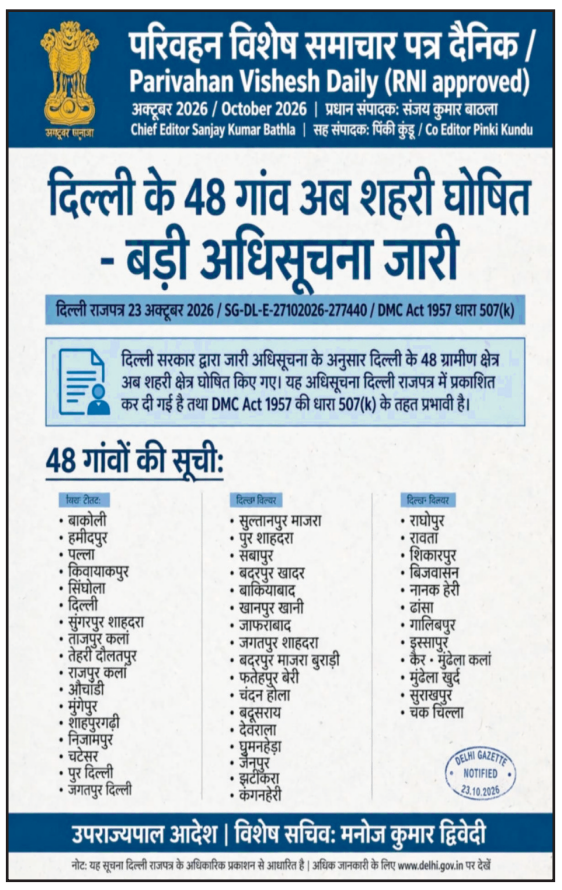
27. फतेहपुर बेरी, 28. चंदन होला

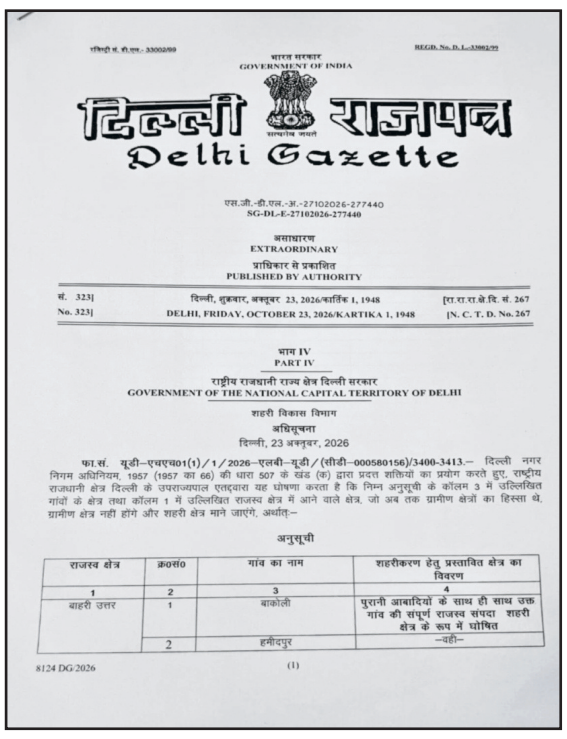
राजस्व क्षेत्र - दक्षिण पश्चिम (20 गांव):

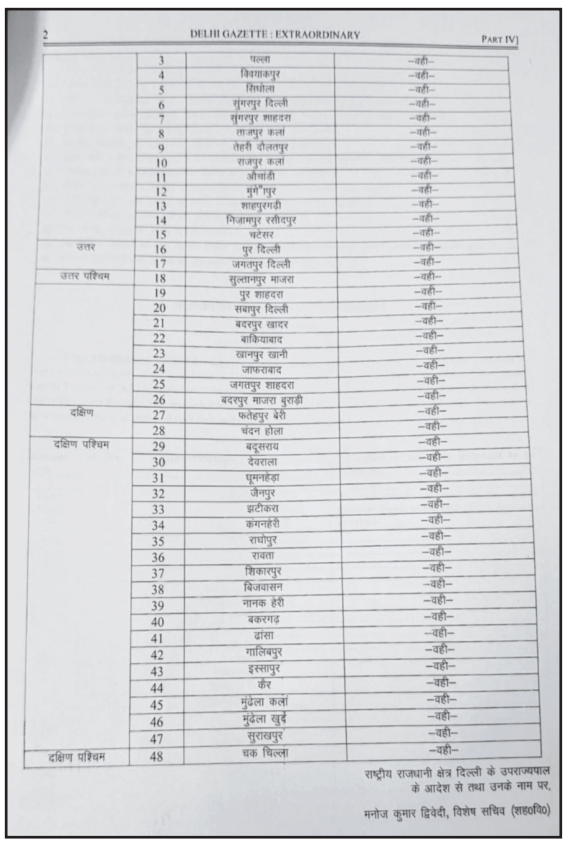
29. बदूसराय, 30. देवराला, 31. घुमनहेड़ा, 32. जैनपुर, 33. झटीकरा, 34. कंगनहेरी, 35. राघोपुर, 36. रावता, 37. शिकारपुर, 38. बिजवासन, 39. नानक हेरी, 40. बकरगढ़, 41. ढांसा, 42. गालिबपुर, 43. इस्सापुर, 44. कैर, 45. मुंढेला कलां, 46. मुंढेला खुर्द, 47. सुराखपुर

राजस्व क्षेत्र - दक्षिण पश्चिम (1 गांव):

48. चक चिल्ला







संपादकीय विश्लेषण - इसका क्या मतलब है जनता के लिए:

- प्रशासनिक बदलाव: ये 48 गांव अब पंचायती राज से हटकर सीधे MCD के शहरी प्रशासन में आएंगे

- विकास का लाभ: शहरीकरण से सड़क, पानी, सीवर, प्रॉपर्टी टैक्स और बिल्डिंग बायलॉज में एकरूपता आएगी, पुरानी आबादियों सहित संपूर्ण राजस्व संपदा को शहरी सुविधाएं मिलेंगी

- जनहित में अपील: जिन किसानों/निवासियों की जमीन इस अधिसूचना में है, वे अपने राजस्व रिकॉर्ड और MCD में म्यूटेशन की प्रक्रिया पर ध्यान दें

यह अधिसूचना दिल्ली के शहरी विस्तार की दिशा में मील का पत्थर है।

Advt No. R&P/324/2026 - दिल्ली विश्वविद्यालय CIE स्कूल भर्ती - परिवहन विशेष - शिक्षा - रोजगार

दिल्ली विश्वविद्यालय में TGT और प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती - CIE एक्सपेरिमेंटल बेसिक स्कूल में 8 पदों पर सुनहरा अवसर

अंतिम तिथि 18 नवंबर 2026, http://B.Ed + CTET अनिवार्य, ऑनलाइन आवेदन शुरू - http://du.ac.in पर करें आवेदन

रिपोर्ट विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र

प्रस्तावना (लीड): दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने अधीन CIE एक्सपेरिमेंटल बेसिक स्कूल में Trained Graduate Teacher (TGT) और Assistant Teacher (Primary) के कुल 08 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या R&P/324/2026 दिनांक 28.10.2026 जारी किया है। यह उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थायी शिक्षक बनना चाहते हैं।

मुख्य बिंदु:

1. पदों का विवरण:

- TGT - 06 पद (Pay Level-07): UR-02, SC-01, OBC-02, EWS-01

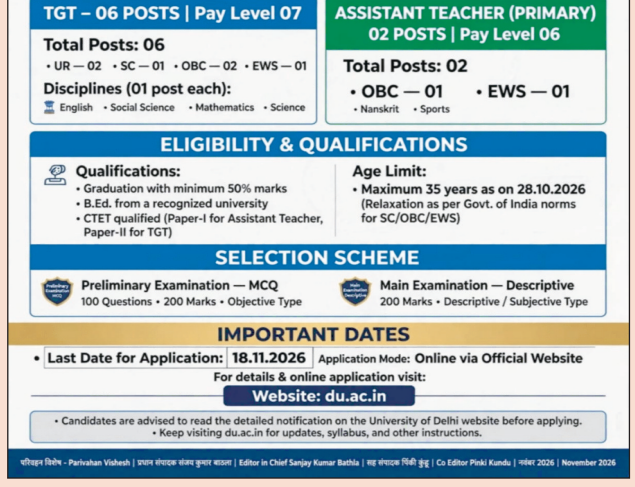
विषयवार: English, Social Science, Mathematics, Science, Sanskrit, Sports (हर विषय में 1 पद, मेरिट श्रेणीवार)

- Assistant Teacher (Primary) - 02 पद (Pay Level-06): OBC-01, EWS-01

2. योग्यता (आपकी PDF के पेज 1-2 के अनुसार):

- TGT के लिए: संबंधित विषय में स्नातक में न्यूनतम 50% (विषय 2 साल पढ़ा हो) या स्नातकोत्तर में 50% + http://B.Ed / 3-वर्षीय http://B.Ed-M.Ed या 4-वर्षीय http://B.El.Ed / http://B.Sc.B.Ed / http://B.A.B.Ed + CTET पेपर-II पास अनिवार्य।

- प्राइमरी के लिए: 50% के साथ सीनियर सेकेंडरी + 2-वर्षीय http://D.El.Ed या http://B.El.Ed या http://D.Ed (Special Education) या Graduation + http://B.Ed + CTET पेपर-I पास + सेकेंडरी स्तर पर हिंदी/अंग्रेजी विषय।



- आयु सीमा: दोनों पदों के लिए 35 वर्ष (SC/ST/OBC/EWS को भारत सरकार नियमानुसार छूट)।

3. चयन प्रक्रिया (2 चरण):

- Stage 1: Preliminary Test (MCQ - 100 प्रश्न, 200 अंक, 2 घंटे): General Awareness, Reasoning, Arithmetic, Pedagogy, English/Hindi Comprehension - यह सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग के लिए है।

- Stage 2: Main Examination (Descriptive - 200 अंक, 2 घंटे): Teaching Aptitude + विषय ज्ञान - इसी से फाइनल मेरिट बनेगी, फिर Skill Test।

- DU में अनुबंध/तदर्थ पर कार्यरत कर्मचारियों को (25.03.2021 तक) हर साल के अनुभव पर 1 अंक (अधिकतम 10 अंक) का लाभ।

4. महत्वपूर्ण तिथियां:

- विज्ञापन तिथि: 28.10.2026

- आवेदन की अंतिम तिथि: 18.11.2026 या Employment News में प्रकाशन से 2 सप्ताह, जो भी बाद में हो।

- आवेदन माध्यम: केवल ऑनलाइन - www.du.ac.in पर Work with DU -> Advertisement-Departments

- किसी भी शुद्धिपत्र के लिए वेबसाइट देखते रहें। तकनीकी समस्या पर: non_teaching_rec@admin.du.ac.in

संपादकीय टिप्पणी: दिल्ली विश्वविद्यालय का CIE स्कूल देश का मॉडल स्कूल माना जाता है। यहाँ TGT और PRT के पदों पर स्थायी नियुक्ति पाना गर्व की बात है। CTET अनिवार्य होने से योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों को ही मौका मिलेगा। सभी इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द आवेदन करें।

42 वर्षों की विशिष्ट सेवा के बाद एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सेवानिवृत्त

'ऑपरेशन सिंदूर' में निर्णायक नेतृत्व और भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता को मजबूत करने में निभाई अहम भूमिका



परिवहन विशेष न्यूज

प्रयागराज: भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम शनिवार को राष्ट्र की 42 वर्षों तक विशिष्ट सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। उनके सेवानिवृत्त होने के साथ ही भारतीय वायुसेना में उनका गौरवशाली सैन्य करियर संपन्न हो गया।

एक कुशल फाइटर पायलट और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट के रूप में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता, युद्धक तैयारियों और आधुनिकीकरण को नई मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वायुसेना प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल में निर्णायक नेतृत्व, सामरिक दक्षता और परिचालन तैयारियों पर विशेष जोर रहा। विशेष रूप से 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपनी युद्ध क्षमता, सटीक कार्रवाई और राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रभावी प्रदर्शन किया।



उनके नेतृत्व में भारतीय वायुसेना की किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता को और मजबूती मिली। सैन्य नेतृत्व के साथ-साथ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का वायु योद्धाओं के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव भी उनकी कार्यशैली की विशेष पहचान रहा। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कर्मी हैं।

उन्होंने युवा अधिकारियों, एयरमैन और कैडेटों को व्यावसायिक दक्षता, जवाबदेही, आत्मविश्वास, पहल और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण का संदेश दिया। उनका मानना रहा कि आने वाली पीढ़ी के वायु योद्धाओं को तैयार करना किसी भी सैन्य संगठन की दीर्घकालिक मजबूती के लिए आवश्यक है।

आधुनिकीकरण के क्षेत्र में उन्होंने स्वदेशीकरण, नवाचार और अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने पर विशेष बल दिया। उनके मार्गदर्शन में भारतीय वायुसेना को तकनीकी रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए।

भारतीय वायुसेना ने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती सरिता सिंह के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनका नेतृत्व, परिचालन संकल्प और वायु योद्धाओं के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा।

जबरन यू-टर्न क्या कानून और संविधान के अनुरूप है?

मार्ग का रणनीतिक सिग्नल बंद करना मोटर यान अधिनियम, सड़क सुरक्षा मानकों और नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन

प्रेषक: पी.एस. बहल, वरिष्ठ नागरिक एवं समाज कल्याण कार्यकर्ता -

1. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि:

स्थान: K.N. काटजू मार्ग - आउटर रिंग रोड, रोहिणी। पहले रणनीतिक सिग्नल से सीधा आवागमन सुगम था। अब सिग्नल हटाकर बाएं मोड़ फिर 500 मीटर आगे राइट-साइड यू-टर्न अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि पीरागढ़ी की ओर से तेज रफ्तार ट्रैफिक और मेट्रो निर्माण कार्य जारी है।

2. संवैधानिक और मूल अधिकारों का प्रश्न:

- अनुच्छेद 21 - जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि सुरक्षित सड़क पर चलना जीवन के अधिकार का हिस्सा है। जबरन खतरनाक यू-टर्न नागरिकों के जीवन को जोखिम में डालता है।

- अनुच्छेद 19(1)(d) - सर्वत्र भ्रमण का अधिकार: बाधा रहित और सुरक्षित आवागमन नागरिक का मूल अधिकार है।

- अनुच्छेद 300A - संपत्ति का अधिकार नहीं, पर सुगम पहुंच: वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों की पहुंच बाधित होना अनुचित।

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 40-46 तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007 के तहत सुगम, बाधा-रहित और सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है।

3. लागू अधिनियम और नियम:

क) मोटर यान अधिनियम, 1988:

- धारा 112 - गति सीमा: यू-टर्न स्थल पर तेज थ्रू-ट्रैफिक के साथ संघर्ष गति सीमा उल्लंघन का कारण बनता है।

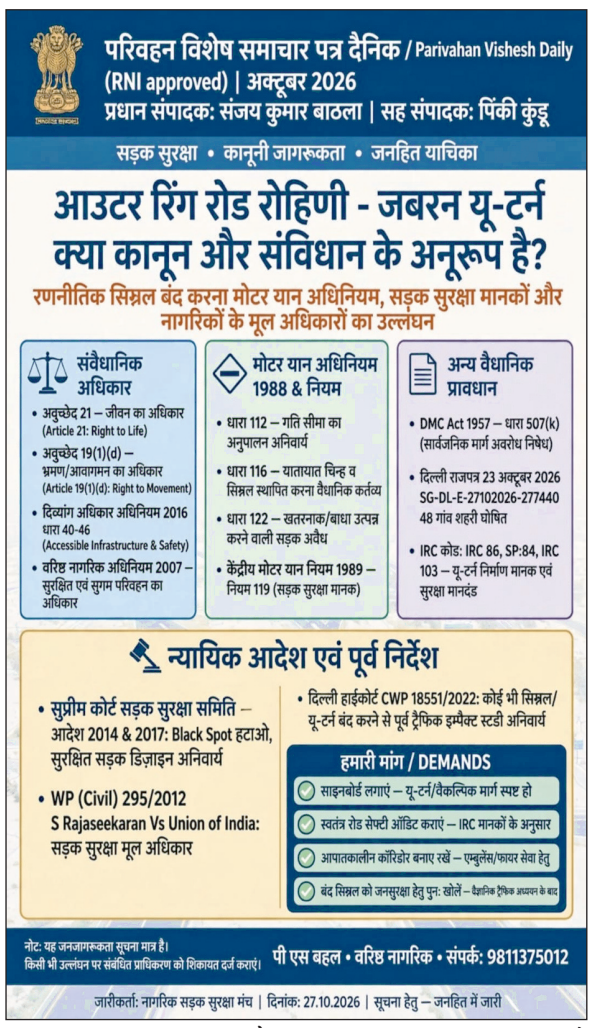
- धारा 116 - यातायात चिन्ह लगाने की शक्ति: राज्य सरकार/प्राधिकरण का कर्तव्य है कि स्पष्ट, दृश्य और मानक साइनबोर्ड लगाए। वर्तमान स्थल पर साइनबोर्ड का अभाव इस धारा का उल्लंघन है।

- धारा 122 - सड़क को खतरनाक स्थिति में छोड़ना: सड़क को ऐसी स्थिति में छोड़ना जिससे खतरा उत्पन्न हो, दंडनीय है।

ख) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 - नियम 119: यातायात नियंत्रण उपकरणों का भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य।

ग) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 507(क): जैसा कि दिल्ली राजपत्र असाधारण संख्या 323 दिनांक 23 अक्टूबर 2026 (SG-DL-E-27102026-277440) में उपराज्यपाल द्वारा 48 गांवों को ग्रामीण से शहरी घोषित किया गया, उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में MCD और PWD का दायित्व है कि शहरी सड़कों पर वैज्ञानिक ट्रैफिक इंजीनियरिंग करे, मनमाने अवरोध नहीं।

घ) IRC कोड - IRC: 86, IRC: SP-84 और IRC: 103: यू-टर्न के लिए न्यूनतम चौड़ाई, दृष्टि दूरी, डीसलेरेशन लेन और पैदल यात्रियों के लिए रिफ्यूज आइलैंड अनिवार्य। रोहिणी में राइट-साइड यू-टर्न इन मानकों पर खरा नहीं उतरता।



4. न्यायिक आदेश और सड़क सुरक्षा समिति के निर्देश:

- सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति (न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन समिति), आदेश 2014 व 2017: सभी राज्यों को निर्देश - "Black Spots को हटाएं, अवैज्ञानिक U-Turn और Speed Breaker न बनाएं, आपातकालीन वाहनों के लिए ग्रीन कॉरिडोर सुनिश्चित करें।"

- सुप्रीम कोर्ट WP (Civil) 295/2012 S. Rajaseekaran Vs Union of India: "जीवन रक्षा के लिए वैज्ञानिक सड़क डिजाइन राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है।"

- दिल्ली हाई कोर्ट आदेश CWP 18551/2022: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को निर्देश - कोई भी सिग्नल बंद करने या रूट बदलने से पहले ट्रैफिक इम्पैक्ट स्टडी और पब्लिक नोटिस अनिवार्य।

5. जनहित में कानूनी मांग - परिवहन विशेष की ओर से:

1. धारा 116 के तहत तुरंत मानक साइनबोर्ड, थर्मोप्लास्टिक मार्किंग और ट्रैफिक कैलमिंग उपाय लगाए जाएं।

2. IRC मानकों के अनुसार स्वतंत्र रोड सेफ्टी ऑडिट कराया जाए और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

3. आपातकालीन वाहनों के लिए विशेष कट और वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, स्कूली बच्चों, महिलाओं के लिए सुरक्षित पैदल क्रॉसिंग सुनिश्चित हो।

4. यदि ट्रैफिक इम्पैक्ट स्टडी नहीं हुई है तो सिग्नल को पुनः खोला जाए अथवा वैज्ञानिक विकल्प के साथ पुनर्मूल्यांकन किया जाए।

निष्कर्ष: सड़क सुरक्षा केवल यातायात व्यवस्था नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत नागरिक के जीवित रहने के मूल अधिकार का प्रश्न है। प्रशासनिक सुविधा के नाम पर असुरक्षित यू-टर्न थोपना न तो मोटर यान अधिनियम के अनुरूप है, न ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के।

प्रदूषण का प्रहार: गर्भस्थ शिशु का जीवन भी खतरे में

डॉ. विजय गर्ग

आज प्रदूषण मानव सभ्यता के सामने खड़ी सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। जिस हवा में हम साँस लेते हैं, जिस पानी को पीते हैं और जिस भोजन से शरीर को पोषण मिलता है, यदि वही दूषित हो जाए तो जीवन की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? प्रदूषण का प्रभाव केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से गर्भ में पल रहा शिशु पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान उसके शरीर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ों और अन्य अंगों का विकास तेजी से हो रहा होता है।

एक नवजात शिशु अपने आसपास के वातावरण को चुन नहीं सकता। वह इस बात का निर्णय नहीं कर सकता कि उसे स्वच्छ हवा मिलेगी या जहरीली। उसका स्वास्थ्य काफी हद तक माँ के स्वास्थ्य, पोषण, गर्भावस्था की परिस्थितियों और व्यापक पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसलिए गर्भस्थ शिशु पर प्रदूषण के प्रभाव को समझना केवल चिकित्सा विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय संवेदनशीलता का भी प्रश्न है।

वायु प्रदूषण: गर्भस्थ जीवन के लिए अदृश्य खतरा

वायु प्रदूषण आज दुनिया के अनेक शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में गंभीर समस्या बन चुका है। वाहनों से निकलने वाला धुआँ, कारखानों का उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधनों का जलना तथा पराली और कचरा जलाना हवा को दूषित करते हैं। इन स्रोतों से निकलने वाले सूक्ष्म कण और जहरीली गैसें मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

इनमें पीएम 2.5 विशेष रूप से चिंताजनक है। ये अत्यंत छोटे कण हैं, जो साँस के साथ फेफड़ों के गहरे हिस्सों तक पहुँच सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में रक्त परिसंचरण को भी प्रभावित कर सकते हैं। गर्भवती महिला के शरीर में इन कणों के संपर्क से सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव और अन्य जैविक परिवर्तन उत्पन्न हो सकते हैं। वैज्ञानिक इन प्रक्रियाओं को गर्भावस्था के प्रतिकूल परिणामों से जोड़कर देख रहे हैं।

विभिन्न अध्ययनों में गर्भावस्था के दौरान वायु प्रदूषण के संपर्क और समय से पहले प्रसव, जन्म के समय कम वजन तथा भ्रूण के विकास में बाधा के बीच संबंध पाया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रदूषित हवा में रहने वाली प्रत्येक महिला को ऐसी समस्या होगी। हालाँकि, लंबे समय तक या अधिक स्तर पर प्रदूषण के संपर्क में रहने से जोखिम बढ़ सकता है। इसी कारण गर्भवती महिलाओं के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार करना सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता होनी चाहिए।

गर्भनाल की भूमिका और प्रदूषण का प्रभाव

गर्भनाल माँ और गर्भस्थ शिशु के बीच जीवनदायी संबंध स्थापित करती है। इसके माध्यम से शिशु को ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं तथा उसके चयापचय से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में सहायता मिलती है। गर्भनाल केवल पोषण पहुँचाने वाली संरचना नहीं है, बल्कि यह कई हानिकारक पदार्थों के विरुद्ध एक आंशिक जैविक अवरोध का कार्य भी करती है।

फिर भी गर्भनाल हर प्रदूषक को रोक नहीं सकती। कुछ रसायन और पर्यावरणीय पदार्थ इसके पार जा सकते हैं या इसके सामान्य कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। शोध में वायु प्रदूषण के संपर्क, गर्भनाल में सूजन और उसके कार्य में संभावित बदलावों के बीच संबंधों का अध्ययन किया गया है।

गर्भावस्था के दौरान ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति भ्रूण के सामान्य विकास के लिए आवश्यक है। यदि गर्भनाल का कार्य प्रभावित होता है, तो शिशु के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो सकती है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान पर्यावरणीय जोखिम कम करना माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है।

समय से पहले जन्म और कम वजन का खतरा

समय से पहले जन्म उस स्थिति को कहते हैं, जब बच्चा गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूरे होने से पहले जन्म लेता है। ऐसे शिशुओं को साँस लेने, शरीर का तापमान बनाए रखने, भोजन पचाने और संक्रमण से लड़ने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। बहुत कम गर्भावधि में जन्म लेने वाले बच्चों को विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है।

जन्म के समय कम वजन भी एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चिंता है। कम वजन वाले शिशुओं में शुरुआती जीवन के दौरान कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम अधिक हो सकता है। उनके विकास की निगरानी और उचित पोषण की विशेष आवश्यकता पड़ सकती है।

वायु प्रदूषण और इन समस्याओं के बीच संबंधों पर अनेक वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। प्रदूषण के संपर्क के अतिरिक्त माँ का पोषण, संक्रमण, रक्तचाप, पहले से मौजूद बीमारियाँ, धूम्रपान और सामाजिक परिस्थितियाँ भी गर्भावस्था के परिणामों को प्रभावित करती हैं। इसलिए किसी एक कारण को सभी मामलों के लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। फिर भी प्रदूषण एक ऐसा जोखिम है जिसे सामूहिक प्रयासों से कम किया जा सकता है।

मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास पर संभावित प्रभाव

गर्भावस्था के दौरान शिशु का मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र तेजी से विकसित होता है। इस प्रक्रिया में कोशिकाओं का निर्माण, उनके बीच संपर्क स्थापित होना और मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों का विकसित होना शामिल है। इन चरणों में पोषण, ऑक्सीजन और स्वस्थ जैविक वातावरण का विशेष महत्व है।

कुछ अध्ययनों में गर्भावस्था के दौरान वायु प्रदूषण के संपर्क और बच्चों के बाद के संज्ञानात्मक तथा तंत्रिका-विकास संबंधी परिणामों के बीच संबंध पाए गए हैं। वैज्ञानिक यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रदूषण से उत्पन्न सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव और अन्य जैविक प्रक्रियाएँ मस्तिष्क के विकास को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं।

हालाँकि, इस क्षेत्र में अभी और शोध की आवश्यकता है। किसी बच्चे के विकास को केवल प्रदूषण के आधार पर समझना सही नहीं होगा, क्योंकि आनुवंशिकता, पोषण, पारिवारिक वातावरण, शिक्षा और सामाजिक परिस्थितियाँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर भी गर्भावस्था के दौरान प्रदूषण कम करना बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए एक समझदारी भरा कदम है।

केवल हवा नहीं, पानी और मिट्टी भी बन सकते हैं खतरा

प्रदूषण की समस्या वायु तक सीमित नहीं है। दूषित पानी, मिट्टी में मौजूद जहरीले पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट और खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले कुछ रासायनिक प्रदूषक भी मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।

सीसा ऐसा विषैला धातु प्रदूषक है, जिसका संपर्क विकासशील मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान सीसे का संपर्क भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकता है। पारा के कुछ रूप भी तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए नुकसानदायक हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ औद्योगिक रसायनों और कीटनाशकों के संपर्क को लेकर भी वैज्ञानिक चिंता व्यक्त करते हैं।



गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ भोजन और रसायनों के अनावश्यक संपर्क से बचाव महत्वपूर्ण है। पुराने रंगों, दूषित धूल, अनुचित तरीके से संभाले गए औद्योगिक पदार्थों और असुरक्षित रासायनिक उत्पादों से सावधानी बरतनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में जल या मिट्टी के दूषित होने की आशंका हो, वहाँ जाँच और सुरक्षित विकल्पों की व्यवस्था करना आवश्यक है।

घर के भीतर का प्रदूषण भी कम गंभीर नहीं

अक्सर यह मान लिया जाता है कि घर के अंदर रहने से प्रदूषण से पूरी तरह बचा जा सकता है। वास्तविकता इससे अलग है। खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन का उपयोग, घर के भीतर धूम्रपान, खराब वेंटिलेशन, धूल, फफूँद और कुछ सफाई उत्पादों से उत्पन्न धुएँ के कारण घर के अंदर की हवा भी दूषित हो सकती है।

विशेष रूप से उन घरों में समस्या गंभीर हो सकती है जहाँ लकड़ी, कोयला, उपले या अन्य ठोस ईंधन का उपयोग पर्याप्त वेंटिलेशन के बिना किया जाता है। इससे उत्पन्न धुआँ गर्भवती महिला के श्वसन और सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।

जहाँ संभव हो, स्वच्छ खाना पकाने वाले ईंधन का उपयोग करना चाहिए। रसोई में उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करना, घर के अंदर धूम्रपान पूरी तरह रोकना और धुएँ के स्रोतों को कम करना उपयोगी उपाय हैं। तेज गंध वाले रसायनों और स्प्रे का अनावश्यक उपयोग भी सीमित करना चाहिए।

गर्भवती महिलाओं के लिए व्यावहारिक सावधानियाँ

प्रदूषण को पूरी तरह व्यक्तिगत प्रयासों से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ सावधानियाँ जोखिम कम करने में मदद कर सकती हैं।

पहला, वायु गुणवत्ता पर ध्यान दें। जब स्थानीय वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो, तब बाहर लंबे समय तक रहने और भारी शारीरिक गतिविधि से बचना उचित है। व्यायाम के लिए स्वच्छ वातावरण और कम प्रदूषण वाले समय का चयन किया जा सकता है।

दूसरा, धुएँ से दूरी बनाएँ। यातायात के अत्यधिक धुएँ वाले स्थानों, कचरा जलाने वाले क्षेत्रों और औद्योगिक उत्सर्जन के निकट अनावश्यक रूप से रुकने से बचें। घर में किसी को भी धूम्रपान न करने दें।

तीसरा, सुरक्षित पानी और भोजन अपनाएँ। विश्वसनीय स्रोत से पेयजल लें और भोजन को साफ-सुथरे तरीके से तैयार करें। फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धोएँ। यदि स्थानीय पानी दूषित होने की आशंका हो, तो संबंधित स्वास्थ्य या जल विभाग की सलाह के अनुसार सुरक्षित विकल्प अपनाएँ।

चौथा, नियमित प्रसवपूर्व जाँच कराएँ। डॉक्टर की सलाह के अनुसार गर्भावस्था की जाँच, पोषण संबंधी मार्गदर्शन और आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्राप्त करें। यदि किसी विशेष रसायन या प्रदूषक के अधिक संपर्क की आशंका हो, तो डॉक्टर को इसकी जानकारी दें।

पाँचवाँ, घर में स्वच्छ वातावरण बनाएँ। जहाँ संभव हो, उचित वेंटिलेशन रखें, धूल कम करें और सुरक्षित सफाई विधियों का उपयोग करें। वायु शोधक कुछ परिस्थितियों में घर के भीतर सूक्ष्म कणों को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे बाहरी प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण का विकल्प नहीं हैं।

मास्क का उपयोग भी परिस्थितियों के अनुसार उपयोगी हो सकता है। अच्छी तरह फिट होने वाला प्रमाणित N95 या समकक्ष रेस्पिरेटर सूक्ष्म कणों के संपर्क को कम कर सकता है, लेकिन सभी गैसों और रासायनिक प्रदूषकों से सुरक्षा नहीं देता। गर्भवती महिला को अपनी विशेष स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

क्या केवल माँ की सावधानी पर्याप्त है?

यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर प्रदूषण से बचने की सलाह गर्भवती महिलाओं को दी जाती है, लेकिन उनसे यह अपेक्षा करना कि वे अकेले ही अपने बच्चे को हर पर्यावरणीय खतरे से बचा लें, न्यायसंगत नहीं है। यदि किसी शहर की हवा जहरीली है, पीने का पानी दूषित है या किसी क्षेत्र में औद्योगिक कचरे का अनुचित निपटान हो रहा है, तो व्यक्तिगत सावधानियों की सीमाएँ स्पष्ट हैं।

स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना शासन, उद्योगों, स्थानीय निकायों और समाज की साझा जिम्मेदारी है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी नीतियों, नियमित निगरानी और नियमों के पालन की आवश्यकता है। गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों जैसे संवेदनशील समूहों की सुरक्षा को सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं में विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।

भारत में प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता

भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, वाहनों की संख्या, निर्माण गतिविधियों, औद्योगिक उत्सर्जन और कुछ क्षेत्रों में कृषि अवशेष जलाने से वायु गुणवत्ता पर दबाव पड़ता है। कई शहरों में सर्दियों के दौरान प्रदूषण की समस्या अधिक गंभीर हो जाती है। मौसम की परिस्थितियाँ, हवा की गति, तापमान और प्रदूषकों के स्थानीय स्रोत भी प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करते हैं।

इस चुनौती से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, उद्योगों में उत्सर्जन नियंत्रण सुनिश्चित करना और निर्माण स्थलों पर धूल कम करना आवश्यक है। पराली और कचरा जलाने के विकल्प उपलब्ध कराना भी महत्वपूर्ण है। किसानों को केवल दंडित करने के बजाय मशीनों, आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और फसल अवशेषों के उपयोग के व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए।

स्कूलों, अस्पतालों, आँगनवाड़ी केंद्रों और गर्भवती महिलाओं की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य केंद्रों में प्रदूषण संबंधी जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। स्थानीय स्तर पर वायु गुणवत्ता की विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध होने से लोग अपनी गतिविधियों की बेहतर योजना बना सकते हैं।

विज्ञान, चिकित्सा और समाज की साझा भूमिका

चिकित्सा विशेषज्ञ गर्भवती महिलाओं को व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन दे सकते हैं, जबकि वैज्ञानिक प्रदूषण के स्रोतों, उनके प्रभावों और नियंत्रण के प्रभावी उपायों पर शोध कर सकते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ और नीति निर्माता प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए योजनाएँ बना सकते हैं। मीडिया और शिक्षण संस्थान लोगों को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जागरूक कर सकते हैं।

इस विषय पर जागरूकता फैलाते समय भय पैदा करने के बजाय विश्वसनीय जानकारी देना आवश्यक है। प्रत्येक गर्भवती महिला को यह समझना चाहिए कि प्रदूषण का संपर्क होने का अर्थ यह नहीं है कि उसके बच्चे को निश्चित रूप से नुकसान होगा। इसी प्रकार, प्रदूषण के जोखिमों को अनदेखा करना भी उचित नहीं है। सही जानकारी, समय पर चिकित्सा देखभाल और प्रदूषण नियंत्रण के सामूहिक प्रयास बेहतर परिणामों की संभावना बढ़ा सकते हैं।

आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी

गर्भ में पल रहा शिशु समाज के भविष्य का प्रतीक है। वह एक ऐसे संसार में जन्म लेने वाला है, जिसे हमने बनाया है और जिसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। यदि हवा दूषित होगी, पानी असुरक्षित होगा और पर्यावरण में जहरीले पदार्थ बढ़ते रहेंगे, तो इसका बोझ वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों दोनों को उठाना पड़ेगा।

विकास आवश्यक है, लेकिन ऐसा विकास जो स्वास्थ्य और पर्यावरण की कीमत पर हो, दीर्घकाल में समाज के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सड़कें, उद्योग, ऊर्जा और आवास के विकास के साथ प्रदूषण नियंत्रण को भी समान महत्व देना होगा। स्वच्छ ऊर्जा, हरित परिवहन, वृक्षारोपण, कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन और पर्यावरणीय नियमों का पालन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

वृक्षारोपण उपयोगी है, लेकिन केवल पेड़ लगाना पर्याप्त नहीं। प्रदूषण के मूल स्रोतों को नियंत्रित करना, मौजूदा वृक्षों और हरित क्षेत्रों की रक्षा करना तथा शहरों की योजना पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाना भी आवश्यक है।

प्रदूषण का प्रहार अदृश्य हो सकता है, लेकिन उसके संभावित प्रभाव वास्तविक और गंभीर हैं। गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी, पौष्टिक भोजन और बेहतर चिकित्सा सेवाएँ आवश्यक हैं। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि वायु प्रदूषण और कुछ रासायनिक प्रदूषकों का संपर्क गर्भावस्था के प्रतिकूल परिणामों के जोखिम से जुड़ा हो सकता है। इसलिए इस खतरे को समय रहते समझना और उसका समाधान करना जरूरी है।

हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि गर्भवती महिलाओं को प्रदूषण से बचाव की जानकारी और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ मिलें। साथ ही, सरकार, उद्योगों और नागरिकों को मिलकर पर्यावरणीय प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

स्वच्छ हवा केवल साँस लेने की सुविधा नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा वास्तव में मानवता के भविष्य की सुरक्षा है। आज पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाया गया प्रत्येक जिम्मेदार कदम आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ, सुरक्षित और बेहतर जीवन देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।

सेवानिवृत्त प्राचार्य | प्रख्यात वैज्ञानिक
स्ट्रीट कौर चंद, एम एच आर
मलोट, पंजाब – 152107

परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक - स्वास्थ्य विशेष कॉलम - भोजन, स्वास्थ्य और जीवनशैली पर जागरूकता

भोजन के साथ टीवी, सेहत से बेवफाई
कविता – सजग भोजन का संदेश | मोबाइल-टीवी छोड़ो, थाली को समय दो

कविः संजय एम तराणेकर, इन्दौर - मध्य प्रदेश



कविता:

थाली में पकवान सजे हैं, आँखें टीवी पर अटकी,
निवाला मुँह तक आता है, सुध-बुध कहीं भटकी।
कभी समाचार-धारावाहिक, मूवी का शोर मचता,
खाने का स्वाद न मिलता, ध्यान कहीं नहीं रहता।
खाना सिर्फ पेट भरना नहीं, ये जीवन का आधार,
हर निवाला स्वाद समझना, सेहत का यह उपहार।
बैठो शांत, सुकून के संग, भोजन का करें सम्मान,
टीवी को थोड़ी छुट्टी देकर, अपनों से करों संवाद।
जल्दी-न हड़बड़ी में खाओ, हर कौर खूब चबाओ,
स्वाद व संतुलन सेहत का, थाली में मेल बिठाओ।
मोबाइल व टीवी छोड़ो यार, भोजन को दो समय,
स्वस्थ शरीर का मंत्र, 'सजग' रहों जीवन सुखमय।

संपादकीय विश्लेषण:

1. **तथ्य** - आज की जीवनशैली का सचः भारत में 70% से अधिक परिवार भोजन के समय टीवी/मोबाइल का उपयोग करते हैं। इससे ओवरईटिंग, अपच और मोटापे की समस्या बढ़ती है।

2. मुख्य बिंदु - कविता क्या सिखाती है:

- माइंडफुल ईटिंगः हर कौर को चबाना, स्वाद को महसूस करना
- डिजिटल डिटॉक्सः भोजन के समय स्क्रीन से दूरी
- परिवार संवादः थाली पर बातचीत से रिश्ते मजबूत
- स्वास्थ्य मंत्रः शांत, सुकून और सम्मान के साथ भोजन

3. वैज्ञानिक आधार: आयुर्वेद में भी 'एकाग्रचित होकर भोजन' को स्वास्थ्य का पहला नियम बताया गया है। ध्यान भटकने से पाचन रस ठीक से नहीं बनते।

4. संपादकीय टिप्पणी: यह कविता केवल कविता नहीं, आज के दौर की स्वास्थ्य चेतावनी है। परिवहन विशेष इस संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लेता है।

दिवाली विशेष रेसिपी कॉलम - स्वस्थ रहें, खुशहाल दिवाली मनाएं

इस दिवाली घर में बनाएं खजूर और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू - सेहत और स्वाद का संगम

बिना चीनी प्राकृतिक मिठास की हेल्दी मिठाई | बाजार की मिलावटी मिठाई को कहें अलविदा

प्रस्तुतकर्ता पिंकी कुंडू सामाजिक परामर्शदाता



मुख्य बिंदु:

- तथ्यः दिवाली पर बाजार की मिठाइयों में मिलावट और ज्यादा चीनी का खतरा बढ़ता है
- विकल्पः खजूर की प्राकृतिक मिठास + मेवों की ऊर्जा = हेल्दी लड्डू
- लाभः शुगर-फ्री, फाइबर युक्त, बच्चों से बुजुर्गों तक सभी के लिए उपयुक्त

सामग्री (4 लोगों के लिए):

- खजूर - 200 ग्राम (बीज निकले हुए)
- बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता - 1/2 कप मिश्रित, बारीक कटे
- घी - 1 छोटा चम्मच
- इलायची पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच
- नारियल बुरादा - 2-3 बड़े चम्मच सजावट के लिए

विस्तृत विधि:

चरण 1: खजूर को गर्म पानी में 10 मिनट भिगो दें ताकि वे नरम हो जाएं।

चरण 2: एक पैन में बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता को हल्का भून लें, खुशबू आने तक। ठंडा होने पर छोटे टुकड़ों में काट लें।

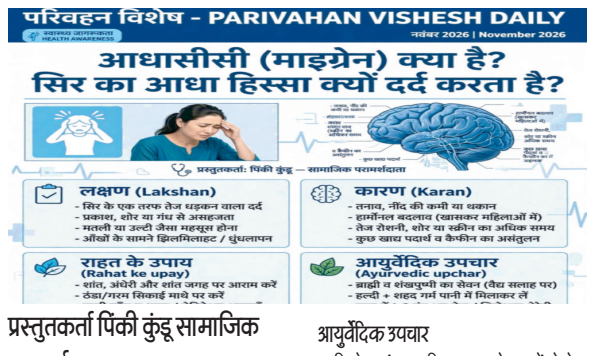
चरण 3: भीगे खजूर को मिक्सी में पीसकर चिकना पेस्ट बना लें।

चरण 4: कड़ाही में घी गर्म करें, खजूर पेस्ट डालकर 2-3 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। फिर कटे ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर मिलाकर अच्छी तरह चलाएं।

चरण 5: गैस बंद कर मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर हाथों पर थोड़ा घी लगाकर छोटे-छोटे लड्डू बना लें। ऊपर से नारियल बुरादा लपेटें।

संपादकीय टिप्पणी: यह रेसिपी केवल मिठाई नहीं, सेहत का उपहार है। बिना चीनी, बिना मैदा - खजूर से आयरन और फाइबर, मेवों से प्रोटीन और हेल्दी फैट। दिवाली विशेष रेसिपी कॉलम में हम ऐसी ही घर की बनी, स्वच्छ मिठाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं।

आधासीसी (माइग्रेन) क्या है? सिर का आधा हिस्सा क्यों दर्द करता है?



प्रस्तुतकर्ता पिंकी कुंडू सामाजिक परामर्शदाता

बार-बार सिरदर्द हो तो इसे नज़रअंदाज़ न करें!

आधासीसी के प्रमुख लक्षण

1. सिर के एक तरफ तेज़ धड़कन जैसा दर्द होना।
2. आँखों के सामने अंधेरा या चमक दिखाई देना।
3. जी मिचलाना या उल्टी होना।
4. रोशनी और तेज़ आवाज़ से परेशानी होना।
5. धूप में जाने या नींद पूरी न होने पर सिरदर्द बढ़ना।

माइग्रेन बढ़ने के कुछ कारण

1. लंबे समय तक भूखे रहना।
2. पर्याप्त नींद न लेना।
3. मानसिक तनाव।
4. शरीर में पानी की कमी।
5. तेज़ रोशनी या तेज़ आवाज़।
6. कुछ विशेष खाद्य पदार्थ।

राहत पाने के लिए क्या करें?

1. शांत और अंधेरे कमरे में आराम करें।
2. माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखें।
3. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँ।
4. समय पर संतुलित भोजन करें।
5. नियमित और पर्याप्त नींद लें।
6. प्रतिदिन हल्का व्यायाम करें।

आयुर्वेदिक उपचार

1. शिरोअभ्यंग – सिर पर हल्के हाथों से तेल की मालिश।
2. शिरोधारा – विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में किया जाने वाला आयुर्वेदिक उपचार।
3. नस्य – वैद्य की सलाह से की जाने वाली आयुर्वेदिक प्रक्रिया।

खानपान में क्या सावधानी रखें?

1. ताज़ी सब्ज़ियाँ और फल खाएँ।
2. दालों और पौष्टिक आहार को शामिल करें।
3. चाय-कॉफी का अधिक सेवन न करें।
4. लंबे समय तक भूखे न रहें।
5. उन खाद्य पदार्थों को पहचानें जिनसे आपको सिरदर्द होता है।

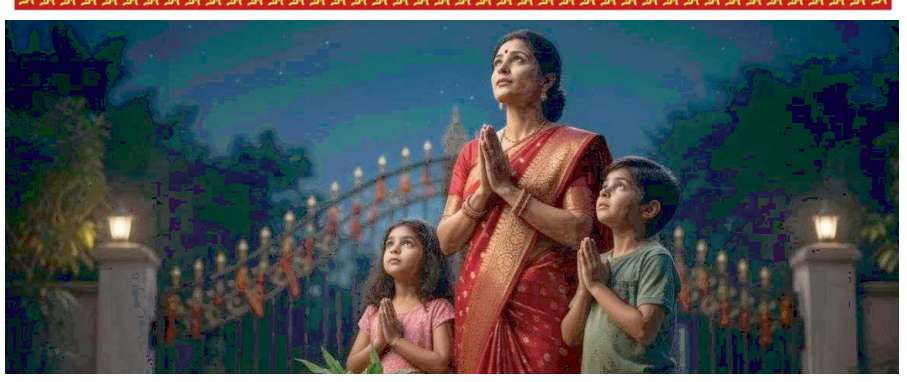
डॉक्टर से कब संपर्क करें? सिरदर्द बार-बार हो या दैनिक कार्यों पर असर पड़ने लगे, तो डॉक्टर से सलाह लें।

अचानक बहुत तेज़ सिरदर्द, हाथ-पैरों में कमजोरी, बोलने में परेशानी या आँखों की रोशनी में अचानक बदलाव होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

याद रखें! माइग्रेन सिर्फ सामान्य सिरदर्द नहीं है। सही जाँच, नियमित दिनचर्या और उचित उपचार से इसे नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है!





Vediccodes
VASTU • NUMEROLOGY • ASTROLOGY
आपके दिन की शुरुआत, पारुल भटनागर के साथ
विशेषज्ञ एस्ट्रो न्यूमेरो वास्तु कंसल्टेंट
परिवहन विशेष News



धन और रिश्तों का दैनिक अंक ज्योतिष भविष्यफल

जानिए दिन की ऊर्जा • संभालिए धन • मजबूत बनाइए रिश्ते

01 नवंबर 2026 | दिन का अंक: 4 — व्यवस्था, अनुशासन, स्थिरता, व्यावहारिकता और निरंतर प्रगति

मूलांक 1

धन व करियर: दिन का अंक 4 आपकी स्वाभाविक नेतृत्व ऊर्जा को अनुशासन और व्यवस्था के साथ काम करने को कहता है। नई पहल को तेजी से आगे बढ़ाने से पहले प्राथमिकताएं, बजट और लंबित जिम्मेदारियां व्यवस्थित करें।
रिश्ते: आप चीजें अपने तरीके से करना चाह सकते हैं, जबकि आज धैर्य और विश्वसनीयता जरूरी है। लगातार सही व्यवहार से प्रतिबद्धता दिखाएं और व्यावहारिक निर्णयों में सामने वाले को शामिल करें।
सावधानी: अधीरता, कठोर नियंत्रण और परिणाम जल्दी पाने के लिए अनावश्यक खर्च से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को स्पष्ट संरचना दें और उसका पहला व्यावहारिक कदम पूरा करें।

मूलांक 2

धन व करियर: दिन 4 आपकी संवेदनशील प्रकृति को व्यावहारिक आधार देता है। केवल अंतर्ज्ञान पर निर्भर रहने के बजाय बिल, बचत, समझौते या संयुक्त धन को ध्यान से जांचें।
रिश्ते: आज सुरक्षा महत्वपूर्ण रहेगी। बार-बार आश्वासन या अनुमान से अधिक छोटे लेकिन भरोसेमंद काम विश्वास बढ़ाएंगे।
सावधानी: असुरक्षा, काम टालने और हर व्यावहारिक निर्णय दूसरे पर छोड़ने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक सरल दिनचर्या बनाएं जो आर्थिक या भावनात्मक स्थिरता बढ़ाए।

मूलांक 3

धन व करियर: दिन 4 आपकी रचनात्मकता और संवाद को संरचना देता है। अच्छे विचार में समयसीमा, बजट और निरंतर क्रियान्वयन जोड़ने पर वह वास्तविक मूल्य दे सकता है।
रिश्ते: आपकी हल्की-फुल्की प्रकृति के सामने आज गंभीर माहौल हो सकता है। गर्मजोशी रखें, लेकिन वादे और व्यावहारिक जिम्मेदारियां भी निभाएं।
सावधानी: बिखरे फोकस, मनोरंजन पर अनावश्यक खर्च और महत्वपूर्ण काम अधूरा छोड़ने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: नया शुरू करने से पहले एक रचनात्मक प्राथमिकता पूरी करें।

मूलांक 4

धन व करियर: आपके मूलांक 4 और दिन के अंक 4 की ऊर्जा एक-दूसरे को बहुत मजबूत करती है। अनुशासन, व्यवस्था, व्यावहारिकता और दीर्घकालिक योजना के लिए श्रेष्ठ दिन है; साथ ही उचित लचीलापन बनाए रखें।
रिश्ते: आज विश्वसनीयता आपकी ताकत है, लेकिन दिनचर्या रिश्ते को सहारा दे—दूसरों पर नियम थोपने का माध्यम न बने।
सावधानी: कठोरता, निराशावाद, अत्यधिक आलोचना और समझदार बदलाव का विरोध करने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक मजबूत आधार बनाएं और जानबूझकर एक उपयोगी बदलाव स्वीकार करें।

मूलांक 5

धन व करियर: दिन 4 आपकी तेज ऊर्जा को धीमा करके निरंतरता पर ध्यान देता है। दिशा बदलने या नए अवसर के पीछे जाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट, समय और खर्च की समीक्षा करें।
रिश्ते: स्वतंत्रता और दिनचर्या में टकराव महसूस हो सकता है। अपनी योजनाएं स्पष्ट बताने से व्यावहारिक असुविधा भावनात्मक समस्या बनने से बच सकती है।
सावधानी: अचानक खरीदारी, वादे भूलने और बिना बताए आखिरी समय में योजना बदलने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: नए रोमांच से पहले एक लंबित जिम्मेदारी पूरी करें।

मूलांक 6

धन व करियर: दिन 4 घर, परिवार और काम में व्यावहारिक सुरक्षा को समर्थन देता है। नियमित खर्च देखें और ऐसी योजना बनाएं जो आराम बनाए रखे लेकिन बचत कमजोर न करे।
रिश्ते: आज प्यार भरोसेमंद कामों से सबसे अच्छी तरह दिखेगा। वादे निभाएं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के जीवन की हर जिम्मेदारी स्वयं न लें।
सावधानी: अधिक जिम्मेदारी, पूर्णता की जिद और सबको आराम देने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक व्यावहारिक देखभाल के काम और समझदार आर्थिक निर्णय से स्थिरता बनाएं।

मूलांक 7

धन व करियर: दिन 4 आपकी विश्लेषणात्मक सोच को ठोस रूप देता है। शोध उपयोगी है, लेकिन आज समझ को व्यावहारिक सिस्टम, समय-सारणी या आर्थिक योजना में बदलना बेहतर रहेगा।
रिश्ते: जिम्मेदारियां भारी लगने पर आप सोच में पीछे हट सकते हैं। भावनात्मक रूप से अनुपस्थित होने के बजाय अपनी जरूरत स्पष्ट बताएं।
सावधानी: अत्यधिक विश्लेषण, अलगाव और पूर्ण निश्चितता के इंतजार में व्यावहारिक कदम टालने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक अच्छी तरह जांचे विचार को सरल और कार्यशील व्यवस्था में बदलें।

मूलांक 8

धन व करियर: दिन 4 आपकी अनुशासित महत्वाकांक्षा के साथ अच्छा मेल खाता है। तुरंत लाभ के बजाय सिस्टम, अनुपालन, बजट और दीर्घकालिक संपत्ति पर ध्यान दें; निरंतर प्रयास स्थिति मजबूत कर सकता है।
रिश्ते: जिम्मेदारियां आपका अधिक ध्यान ले सकती हैं। दक्षता और नियंत्रण को गर्मजोशी या साझा निर्णय का विकल्प न बनने दें।
सावधानी: काम में अत्यधिक डूबने, कठोर अपेक्षाएं और धन को प्रतिबद्धता का माप बनाने से बचें।
दिन बेहतर बनाएं: एक दीर्घकालिक प्राथमिकता सुरक्षित करें और एक व्यक्तिगत रिश्ते के लिए समय निकालें।

मूलांक 9

धन व करियर: दिन 4 आपकी उदार और जोशीली ऊर्जा को व्यावहारिक आधार देता है। लंबित जिम्मेदारियां पूरी करें, संसाधन व्यवस्थित करें और समय व धन कहां जा रहा है उसकी स्पष्ट सीमा बनाएं।
रिश्ते: आप दूसरों की हर समस्या हल करना चाह सकते हैं। व्यावहारिक सहयोग दें, लेकिन अपनों को अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाने दें।
सावधानी: हर किसी को बचाने की कोशिश, अपराधबोध में खर्च और ऐसे बोझ को पकड़े रखने से बचें जो अब आपका नहीं है।
दिन बेहतर बनाएं: एक अधूरा विषय व्यवस्थित करें और एक अनावश्यक जिम्मेदारी छोड़ें।

कॉल / व्हाट्सऐप: 8750075550 | वेबसाइट: www.vediccodes.in | @vediccodes

Vediccodes - Your vibrations... our solutions

अहोई अष्टमी व्रत : मातृत्व की ममता, संतान की दीर्घायु और सुख-समृद्धि का पावन पर्व

1 नवंबर 2026, रविवार को मनाया जाएगा अहोई अष्टमी का पर्व – तारा दर्शन के बाद पूर्ण होगा माताओं का व्रत, अहोई माता से संतान की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना

अहोई अष्टमी 2026 : तिथि एवं पूजा का शुभ मुहूर्त
पर्व: रविवार, 1 नवंबर 2026
अष्टमी तिथि प्रारंभ: 1 नवंबर, दोपहर 2:51 बजे
अष्टमी तिथि समाप्त: 2 नवंबर, दोपहर 1:10 बजे
पूजा का शुभ मुहूर्त: शाम 5:36 बजे से 6:54 बजे तक
तारा दर्शन का समय: लगभग शाम 6:00 बजे
व्रत का उद्देश्य: संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और मंगलमय भविष्य की कामना।

भारतीय संस्कृति में मातृत्व को सृष्टि की सबसे पवित्र और महान भावनाओं में स्थान दिया गया है। माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है, उसका त्याग असीमित होता है और अपनी संतान के सुख, सुरक्षा तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए उसकी प्रार्थनाएँ जीवनभर चलती रहती हैं। इसी मातृभाव, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का सुंदर प्रतीक है अहोई अष्टमी का पावन पर्व। यह केवल एक धार्मिक व्रत नहीं, बल्कि माँ और संतान के बीच अटूट प्रेम, भावनात्मक जुड़ाव और पारिवारिक संस्कारों का उत्सव भी है।

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला अहोई अष्टमी का पर्व उत्तर भारत सहित देश के अनेक क्षेत्रों में विशेष श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह व्रत करवा चौथ के लगभग चार दिन बाद और दीपावली से करीब एक सप्ताह पहले आता है। वर्ष 2026 में यह पर्व 1 नवंबर, रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन माताएँ अपनी संतानों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुख-समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना से अहोई माता का व्रत रखती हैं। संध्या के समय विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने के बाद तारों के दर्शन कर व्रत का पारण किया जाता है।

मातृत्व की आस्था और संतान के प्रति समर्पण

अहोई अष्टमी का सबसे बड़ा महत्व माँ की उस भावना में छिपा है, जिसमें वह अपनी संतान के कल्याण के लिए दिनभर उपवास रखती है और ईश्वर से उसके सुरक्षित एवं सुखी जीवन की प्रार्थना करती है। परंपरागत रूप से यह व्रत माताएँ अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए रखती थीं, लेकिन बदलते सामाजिक परिवेश में अब यह पुत्र और पुत्री दोनों के कल्याण के लिए किया जाता है। यह परिवर्तन भारतीय समाज में समानता और संतान के प्रति एक समान स्नेह की भावना को भी दर्शाता है।

माँ के लिए संतान का सुख ही सबसे बड़ा सुख होता है। बच्चे के जीवन में आने वाली छोटी-सी परेशानी भी माँ को विचलित कर देती है। ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत उसकी आस्था और विश्वास को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनता है। इस दिन माताएँ यह संकल्प लेती हैं कि वे अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार और उज्ज्वल भविष्य के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगी।

अहोई माता की पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा

अहोई अष्टमी के व्रत के पीछे एक प्रचलित पौराणिक लोककथा है, जो अनजाने में हुई भूल, पश्चाताप, क्षमा और मातृत्व की करुणा का संदेश देती है।

कथा के अनुसार, प्राचीन समय में एक साहूकार अपनी पत्नी और सात पुत्रों के साथ रहता था। दीपावली के कुछ दिन पहले साहूकार की पत्नी घर की मरम्मत और सजावट के लिए मिट्टी लेने जंगल गई। वहाँ मिट्टी खोदते समय उसके फावड़े से अनजाने में एक साही के बच्चे को चोट लग गई और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से वह अत्यंत दुखी हुई। लोककथा के अनुसार, इसके बाद उसके सातों पुत्रों पर संकट आया और उनकी मृत्यु हो गई।

पुत्रों के वियोग में साहूकारनी अत्यंत व्याकुल रहने लगी। उसे अपनी अनजाने में हुई भूल का पश्चाताप होने लगा। उसने अपनी पीड़ा एक वृद्ध महिला और साधु के सामने व्यक्त की। उसे अहोई माता की आराधना करने, अपनी भूल के लिए पश्चाताप करने और श्रद्धापूर्वक व्रत रखने का मार्ग बताया गया।

साहूकारनी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अहोई माता का व्रत किया तथा अपनी संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसकी भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर माता ने उसकी मनोकामना पूरी की और उसके परिवार में फिर से खुशियाँ लौट आईं। तभी से अहोई अष्टमी का व्रत संतान की रक्षा, मातृत्व की ममता और क्षमा की भावना से जुड़ा माना जाने लगा।

यह कथा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि मनुष्य को प्रकृति और जीव-जंतुओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। अनजाने में हुई गलती का पश्चाताप करना और भविष्य में ऐसी भूल न दोहराने का संकल्प लेना ही सच्चे मानवीय मूल्यों की पहचान है।

कैसे की जाती है अहोई माता की पूजा?

अहोई अष्टमी के दिन प्रातःकाल माताएँ स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और संतान की सुख-समृद्धि तथा दीर्घायु के लिए व्रत का संकल्प लेती हैं। परंपरा के अनुसार अनेक महिलाएँ निर्जला व्रत रखती हैं, जबकि कुछ महिलाएँ अपनी शारीरिक क्षमता और पारिवारिक परंपरा के अनुसार फलाहार करती हैं।

संध्या के समय पूजा की विशेष तैयारी की जाती है। घर की दीवार पर गेरू या अन्य प्राकृतिक रंगों से अहोई माता का चित्र बनाया जाता है अथवा पूजा के लिए तैयार चित्र स्थापित किया जाता है। इसमें अहोई माता, साही और उसके बच्चों के प्रतीकात्मक चित्र बनाए जाते हैं। कुछ परंपराओं में सात पुत्रों और सात तारों का भी विशेष महत्व माना जाता है।

पूजा की थाली में रोली, अक्षत, फूल, दीपक, जल से भरा कलश, दूध, मिठाई, हलवा, पूड़ी और अन्य पारंपरिक पूजन सामग्री रखी जाती है। चाँदी की अहोई या अन्य पारंपरिक प्रतीक भी कई परिवारों में पूजा का हिस्सा होते हैं।

संध्या के समय दीप प्रज्वलित करके अहोई माता की पूजा की जाती है। महिलाएँ अहोई माता को रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करती हैं तथा व्रत कथा का श्रवण करती हैं। इसके बाद संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन में सफलता के लिए प्रार्थना की जाती है।

जब आकाश में तारे दिखाई देने लगते हैं, तब माताएँ तारों के दर्शन करके उन्हें जल अर्पित करती हैं और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार व्रत का पारण करती हैं। कुछ स्थानों पर चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलने की परंपरा भी प्रचलित है।



तारा दर्शन का विशेष धार्मिक महत्व

अहोई अष्टमी के व्रत में तारों का विशेष महत्व है। जिस प्रकार करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद खोला जाता है, उसी प्रकार अहोई अष्टमी में तारों के दर्शन के बाद व्रत खोलने की परंपरा है। आकाश में चमकते तारे आशा, विश्वास और अनंतता के प्रतीक माने जाते हैं।

माताएँ तारों की ओर देखकर अपने बच्चों के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती हैं। इस क्षण में माँ की भावनाएँ और उसकी प्रार्थना इस पर्व को विशेष आध्यात्मिक महत्व प्रदान करती हैं।

वर्ष 2026 में दिल्ली के लिए अहोई माता की पूजा का शुभ समय शाम 5:36 बजे से 6:54 बजे तक निर्धारित है और तारा दर्शन का अनुमानित समय शाम 6 बजे है। हालाँकि, तारों के वास्तविक दिखाई देने का समय मौसम और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। इसलिए स्थानीय पंचांग और आकाश में तारों के दर्शन को ध्यान में रखना चाहिए।

सिर्फ व्रत नहीं, जीव-जंतुओं के प्रति करुणा का संदेश भी

अहोई अष्टमी की कथा में साही जैसे वन्य जीव का उल्लेख इस पर्व को पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण से भी जोड़ता है। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ और सुविधाओं के लिए प्रकृति तथा जीव-जंतुओं को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए।

आज जब जंगलों का क्षेत्र घट रहा है, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहे हैं और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ रहा है, तब इस पर्व का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। हमें पशु-पक्षियों के प्रति दया, संवेदना और संरक्षण की भावना विकसित करनी चाहिए।

धार्मिक आस्था का वास्तविक स्वरूप तभी सार्थक होता है, जब वह हमारे व्यवहार में करुणा और जिम्मेदारी के रूप में दिखाई दे। किसी जीव को अनावश्यक कष्ट न पहुँचाना, प्रकृति की रक्षा करना और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहना भी धर्म का ही हिस्सा है।

बदलते समय में अहोई अष्टमी की प्रासंगिकता

आज का जीवन पहले की अपेक्षा अधिक व्यस्त और चुनौतीपूर्ण हो गया है। नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, शहरी जीवन और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच भी महिलाएँ अपनी परंपराओं और संस्कारों को जीवित रखे हुए हैं। आधुनिक तकनीक ने पूजा-पाठ के माध्यमों को बदल दिया है। अब महिलाएँ ऑनलाइन व्रत कथा सुनती हैं, डिजिटल माध्यमों से पूजा की जानकारी प्राप्त करती हैं और दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों के साथ भी इस पर्व की खुशियाँ साझा करती हैं।

लेकिन इन परिवर्तनों के बावजूद अहोई अष्टमी की मूल भावना आज भी वही है—माँ का निस्वार्थ प्रेम और अपनी संतान के कल्याण की कामना।

इस पर्व का एक सामाजिक पक्ष भी है। महिलाएँ सामूहिक रूप से पूजा करती हैं, एक-दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करती हैं और पारिवारिक परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुँचाती हैं। इससे परिवारों में आपसी सहयोग, आत्मीयता और सामाजिक एकता की भावना मजबूत होती है।

माँ की सेहत भी उतनी ही महत्वपूर्ण

अहोई अष्टमी का व्रत श्रद्धा और विश्वास का विषय है, लेकिन इसके साथ महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। हर महिला की शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं। गर्भवती महिलाओं, मधुमेह, रक्तचाप या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही महिलाओं को निर्जला उपवास रखने से पहले चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। व्रत का उद्देश्य संतान के कल्याण की कामना है, इसलिए माँ का स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है।

परिवार के सदस्यों को भी महिलाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके स्वास्थ्य और सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। मातृत्व का सम्मान केवल एक दिन के व्रत तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि माँ के स्वास्थ्य, सम्मान, सुरक्षा और खुशियों की जिम्मेदारी पूरे परिवार की होनी चाहिए।

मातृत्व का सम्मान ही समाज की सच्ची संस्कृति

अहोई अष्टमी हमें यह समझने का अवसर देती है कि माँ और संतान का संबंध केवल जन्म तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह जीवनभर प्रेम, विश्वास, त्याग और जिम्मेदारी से जुड़ा रहता है। माँ अपने बच्चों को जन्म देने के साथ-साथ उन्हें संस्कार, शिक्षा और जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है।

इस पर्व का संदेश यह भी है कि संतान की दीर्घायु की कामना के साथ उसके अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्यों, शिक्षा और जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना को भी महत्व दिया जाना चाहिए। माता-पिता का दायित्व केवल बच्चों की शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण तक विस्तृत है।

आज समाज में बाल सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सम्मान और समान अवसर जैसे विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अहोई अष्टमी के अवसर पर हमें यह संकल्प भी लेना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण, बेहतर शिक्षा, पौष्टिक आहार और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें।

अंततः अहोई अष्टमी मातृत्व की उस महान भावना का उत्सव है, जिसमें माँ अपनी संतान के सुख और सुरक्षित भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। यह पर्व हमें प्रेम, त्याग, क्षमा, करुणा और पारिवारिक एकता का संदेश देता है। साथ ही यह याद दिलाता है कि माँ का सम्मान और संतान का संरक्षण किसी एक धार्मिक अवसर की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का नैतिक कर्तव्य है।

आइए, इस अहोई अष्टमी पर हम केवल व्रत और पूजा तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी संतानों को अच्छे संस्कार देने, बेटा-बेटी में समानता रखने, प्रकृति एवं जीव-जंतुओं की रक्षा करने और परिवार में प्रेम तथा सम्मान का वातावरण बनाए रखने का संकल्प भी लें।

अहोई माता सभी संतानों को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख, शांति और उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद प्रदान करें। सभी माताओं को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ।

सरदार पटेल के आदर्शों को आत्मसात कर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत बनाने में योगदान दें युवा : मोहन लाल कौशिक

झज्जर में रन फॉर यूनिटी के माध्यम से दिया एकता, अखंडता और राष्ट्रप्रेम का संदेश







हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन मोहन लाल कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को किया रवाना, युवाओं को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ
डीसी वर्षा खांगवाल की अध्यक्षता में महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम में आयोजित हुआ जिला स्तरीय समारोह

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 31 अक्टूबर

देश की एकता और अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को झज्जर के महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम परिसर में रन फॉर यूनिटी एवं राष्ट्रीय एकता शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में युवाओं और गणमान्य व्यक्तियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए देश की एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे को बनाए रखने का संकल्प लिया।

जिला स्तरीय समारोह में हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन मोहन लाल कौशिक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता डीसी वर्षा खांगवाल ने की। भाजपा जिलाध्यक्ष विकास वाल्मीकि की भी गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मोहन लाल कौशिक सहित अन्य अतिथियों द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन करने के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने उपस्थित युवाओं एवं प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। उन्होंने सभी से देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि मोहन लाल कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। इस दौरान अतिथिगण ने स्वयं भी दौड़ में भागीदारी करते हुए युवाओं का उत्साहवर्धन किया। स्टेडियम परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों ने एकजुटता, अनुशासन, राष्ट्रप्रेम और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया।

सरदार पटेल का जीवन राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा

श्री कौशिक ने कहा कि समारोह का उद्देश्य युवा पीढ़ी को सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन, विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान से परिचित कराना तथा राष्ट्रीय एकता की भावना को और अधिक मजबूत करना रहा। उन्होंने बताया कि सरदार पटेल ने देश की रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, नेतृत्व क्षमता और सामूहिक प्रयासों से बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है।

इस अवसर पर एसडीएम झज्जर रवि मीणा, सीटीएम ऋचु, जिला शिक्षा अधिकारी रतींद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और युवा प्रतिभागी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंच संचालन प्रवक्ता संजय शर्मा ने किया।

पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाणपत्र पहली नवंबर से होंगे जमा : डीटीओ

जिला के खजाना एवं उपखजाना कार्यालयों में जमा करवा सकेंगे प्रमाणपत्र

स्मार्टफोन से ऑनलाइन जमा करने की भी सुविधा
*जिला कोषाधिकारी ने पेंशनभोगियों से की समय रहते प्रमाणपत्र जमा करवाने की अपील

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 31 अक्टूबर। जिला खजाना कार्यालय एवं उपखजाना कार्यालयों से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाणपत्र पहली नवंबर से जमा किए जाएंगे। पेंशनभोगी संबंधित खजाना कार्यालयों के अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करवा सकते हैं। यह जानकारी जिला कोषाधिकारी संजय फोगाट ने दी।

कॉमन सर्विस सेंटर और डाकघरों में भी मिलेगी सुविधा

जिला कोषाधिकारी संजय फौगाट ने बताया कि पेंशनभोगी अपने जीवन प्रमाणपत्र कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से भी ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा डाकघरों द्वारा घर पर भी जीवन प्रमाणपत्र जमा करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र जमा करवाने की सुविधा स्मार्टफोन के माध्यम से भी उपलब्ध है और इस प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

स्मार्टफोन से घर बैठे जमा कर सकते हैं प्रमाणपत्र

खजाना अधिकारी संजय फोगाट ने बताया कि पेंशनभोगी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य स्मार्टफोन के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकता है। इसके लिए मोबाइल फोन में जीवन प्रमाण फेस ऐप और आधार फेस आईडी दोनों एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होंगी। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी करके पेंशनभोगी का जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि खजाना कार्यालयों में शुरुआती दिनों में अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए पेंशनभोगी ऑनलाइन एवं अन्य उपलब्ध माध्यमों का लाभ उठाएं। विशेष रूप से अधिक उम्र के बुजुर्ग पेंशनभोगियों को कार्यालय में स्वयं आने की परेशानी से बचाने के लिए वैकल्पिक सुविधाओं का उपयोग करने की सलाह दी।

ये दस्तावेज साथ लाना जरूरी

जिला कोषाधिकारी ने बताया कि खजाना कार्यालय में जीवन प्रमाणपत्र जमा करवाने आने वाले पेंशनभोगी अपने साथ आधार कार्ड की मूल प्रति, पैन कार्ड और पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) की फोटो प्रति अवश्य लेकर आएं। इसके अलावा पेंशन खाते से जुड़े मोबाइल नंबर वाला फोन भी साथ रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ओटीपी के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जा सके। उन्होंने सभी पेंशनभोगियों से निर्धारित समय पर अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करवाने की अपील की।

दिल्ली की सीमा में आज से बीएस-6 से नीचे के वाहन की नो एंट्री : डीटीओ

1 नवंबर से 30 जनवरी 2027 तक लागू रहेंगे नए प्रतिबंध, बाहरी राज्यों में पंजीकृत मालवाहक वाहनों और बसों पर भी लागू होगा नियम*
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई - डीटीओ रवीश हुड्डा



बहादुरगढ़, 31 अक्टूबर। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने वाहनों के आवागमन को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। इसके तहत रविवार 1 नवंबर से दिल्ली में बीएस-6 से नीचे मानक वाले बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 30 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा। इसके दायरे में मालवाहक वाहन और बसें भी शामिल हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी जिला परिवहन अधिकारी रवीश हुड्डा ने शनिवार को यहां दी।

डीटीओ ने बताया कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किए जा रहे इन दिशा-निर्देशों के प्रति वाहन चालकों और परिवहन संचालकों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रवेश करने से पहले वाहन चालक अपने वाहन का उत्सर्जन मानक अवश्य जांच लें। बीएस-6 से नीचे के मानक वाले दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहन लेकर दिल्ली की सीमा में प्रवेश न करें, ताकि कार्रवाई और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।

इन वाहनों को प्रतिबंध से रखा गया है बाहर

डीटीओ रवीश हुड्डा ने बताया कि नए दिशा-निर्देशों के तहत इलेक्ट्रिक (ईवी), सीएनजी और एलएनजी से संचालित वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं और सरकारी संप्रभु कर्तव्यों के निर्वहन में लगे वाहनों को भी इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।

उन्होंने बस संचालकों, मालवाहक वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट यूनियनों से आग्रह किया कि वे नए नियमों की जानकारी अपने सभी वाहन चालकों तक पहुंचाएं।

प्रदूषण नियंत्रण में वाहन चालक निभाएं जिम्मेदारी: रवीश हुड्डा

डीटीओ रवीश हुड्डा ने कहा कि वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में शामिल है। ऐसे में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नियमों की पालना सुनिश्चित करें और दिल्ली में प्रवेश से पहले अपने वाहन की पात्रता की जांच अवश्य कर लें।

प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध : डीसी

डीसी वर्षा खांगवाल ने दिए निर्देश-पटाखों के निर्माण से लेकर भंडारण, बिक्री और आतिशबाजी तक पर रोक; ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी नहीं खरीद सकेंगे पटाखे
आदेशों की अवहेलना करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 31 अक्टूबर।

एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने और आमजन के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पटाखों को लेकर सख्त आदेश जारी किए गए हैं। यह जानकारी डीसी वर्षा खांगवाल ने शनिवार को दी। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार एनसीआर क्षेत्र में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और आतिशबाजी पर तुरंत प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से भी पटाखों की बिक्री और डिलीवरी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

प्रदूषण की स्थिति नियंत्रित रखने के लिए पटाखों के उत्पादन से लेकर बिक्री पर रोक

डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के साथ-साथ नागरिकों को प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है।



एनसीआर क्षेत्र में पटाखों के उपयोग से निकलने वाला धुआं और हानिकारक कण वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। ऐसे में प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पटाखों के उत्पादन से लेकर उनकी बिक्री और उपयोग तक पर प्रतिबंध लगाया गया है।

पटाखों की ऑनलाइन ऑर्डर और डिलीवरी पर भी रहेगी रोक

डीसी वर्षा खांगवाल ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध केवल बाजारों में पटाखों की बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाली बिक्री और डिलीवरी पर भी लागू होगा। कोई भी व्यक्ति या कारोबारी ऑनलाइन माध्यम से पटाखों का ऑर्डर, बिक्री या आपूर्ति नहीं कर सकेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित की जाए और प्रतिबंधित गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए।

प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सतर्क

डीसी ने बताया कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी पत्र के माध्यम से राज्य सरकार के प्रतिबंध संबंधी आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। एनसीआर क्षेत्र में सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लागू किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, विक्रेताओं और अन्य संबंधित पक्षों के विरुद्ध नियामानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पर्यावरण संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करें नागरिक: डीसी

डीसी वर्षा खांगवाल ने आमजन से अपील की कि वे सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और पटाखों की खरीद-बिक्री एवं आतिशबाजी से दूर रहें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ हवा और बेहतर पर्यावरण बनाए रखना केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। नागरिकों के सहयोग से ही वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के प्रयास सफल हो सकते हैं।

नवभारत के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान अतुलनीय: ओम प्रकाश धनखड़

पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
बादली स्थित चौ.धीरपाल राजकीय महाविद्यालय में दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ







बादली, 31 अक्टूबर।

पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल राष्टीय एकता के अनोखे शिल्पकार थे। उन्होंने देश के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोते हुए नव भारत का निर्माण करने में अतुलनीय भूमिका निभाई। उन्होंने एक भारत, श्रेष्ठ भारत के सपने को मूर्त रूप दिया, जिसके लिए राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। पूर्व मंत्री शनिवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर बादली स्थित चौ.धीरपाल राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं को संबोधित कर रहे थे। इस उपरांत उन्होंने उपस्थितजनों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर एसडीएम विशाल कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि ओम प्रकाश धनखड़ ने महाविद्यालय बादली से रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी दौड़ लगाई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता को समर्पित रन फॉर यूनिटी आमजन में आपसी सहयोग व सौहार्दपूर्ण व्यवहार के साथ ही राष्ट्र की एकता व अखंडता का संदेश देते हुए उद्देश्यों की सार्थकता को सिद्ध कर रही है। रन फॉर यूनिटी महाविद्यालय बादली से शुरू होकर देवीलाल द्वार बादली में आकर समाप्त हुई।

देशभक्त पटेल के जीवन चरित्र से प्रेरणा ले युवा पीढ़ी: ओमप्रकाश धनखड़

मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने उपस्थित युवाओं को कहा कि हमें आज के दिन राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। यही हमारी ओर से सरदार वल्लभभाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को देशभक्त पटेल के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए तभी हमारा समाज व देश तरक्की करेगा। उन्होंने विद्यार्थियों व युवाओं को इस पुनीत अभियान में भागीदार बनने पर उनका उत्साहवर्धन किया।

इस अवसर पर नायब तहसीलदार अरविंद, महाविद्यालय के प्राचार्य आनंद कादियान, गांव बादली के सरपंच आनंद गुलिया सहित विनोद बाढ़सा, अमित गुभाना, सीमा लाडपुर, भूपेंद्र यादव, सुरेंद्र गुभाना, श्यामपाल विजय बादली सहित गांव बादली के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

समाज की एकजुटता और राजनीतिक ताकत मजबूत करने के लिए सभाओं का गठन जरूरी : सतबीर वर्मा



परिवहन विशेष न्यूज

हरियाणा/हिसार (राजेश सलूजा) खागा तहसील में आयोजित काकुत्स समाज सम्मेलन में काकुत्स महाराज एवं संत नामदेव जयंती दर्जी, रोहिल्ला एवं टांक क्षेत्रीय समाज के सम्मानित सदस्यों द्वारा बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। सम्मेलन में समाज की एकता, संगठनात्मक मजबूती, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक उत्थान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से नामदेव सभा हरियाणा के अध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा, दिल्ली से दयानंद रोहिल्ला, मध्यप्रदेश के पूर्व चेयरमैन सुनील महेश्वरी, राजेंद्र नामदेव, उर्मिला नामदेव, दिलीप नामदेव, राकेश काकुत्स तथा उपाध्यक्ष भरत छिपा ने अपने विचार रखे।

इस अवसर पर हरियाणा से पहुंचे नामदेव सभा के अध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा ने अपने संबोधन में समाज को संगठित और सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज की एकजुटता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। समाज को अपनी राजनीतिक ताकत का अहसास करवाने के साथ-साथ सामाजिक और संगठनात्मक स्तर पर भी मजबूत होना होगा। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में समाज की सभाओं का गठन करना बेहद जरूरी है, ताकि समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सामूहिक रूप से विचार-विमर्श कर उचित सामाजिक निर्णय लिए जा सकें।

वर्मा ने विशेष रूप से अपील की कि समाज की सभाओं में युवाओं और महिलाओं को भी उचित भागीदारी दी जाए। युवा समाज की ऊर्जा और महिलाएं संगठन की महत्वपूर्ण शक्ति हैं। दोनों की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक संगठन को नई दिशा और मजबूती मिल सकती है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत सामाजिक आधार तैयार किया जा सके।

सम्मेलन में काकुत्स समाज के प्रदेश अध्यक्ष केशवलाल नामदेव, जगनंदन नामदेव, पार्षद श्रवण नामदेव, पूर्व पार्षद सुखलाल, रामनरेश नामदेव, संजीव नामदेव, जयसिंह नामदेव सहित अन्य गणमान्य सदस्यों ने उपस्थित अतिथियों एवं समाज के लोगों का सम्मान किया। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने आपसी भाईचारे, एकता और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया।

'ऑपरेशन सिंदूर' में निर्णायक नेतृत्व और भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता को मजबूत करने में निभाई अहम भूमिका

सीजेआई सूर्यकांत ने दिल्ली हाईकोर्ट की तारीफ़ की, कहा- हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का बहुत-सा बोझ कम किया

रिपोर्ट विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने शुक्रवार को कहा कि अन्य हाई कोर्ट्स की तुलना में दिल्ली हाकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का अत्यधिक बोझ कम करता है।

CJI ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर अपने सामने पेश होने वाले वकीलों को याद दिलाता है कि दिल्ली हाईकोर्ट बिल्कुल पास ही है और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँचने से पहले ही उन्हें वहां से राहत मिल सकती है।

CJI दिल्ली हाईकोर्ट की डायमंड जुबली के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने 60 साल पूरे किए हैं। यह कार्यक्रम दिल्ली हाईकोर्ट के S ब्लॉक स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया।

CJI ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में स्थित होने के कारण दिल्ली हाईकोर्ट पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि सरकारी अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक जवाबदेही से जुड़े मामले अक्सर यहां की अदालतों में आते रहते हैं।

उन्होंने कहा कि शहर के विस्तार व्यापार में वृद्धि और पिछले कुछ वर्षों में मुकदमों की संख्या बढ़ने के साथ दिल्ली हाईकोर्ट की जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई हैं।

उन्होंने कहा, 'जो अदालत कभी सिर्फ चार जजों से शुरू हुई थी, वह आज एक ऐसा संस्थान बन गई है, जो कई तरह के और बेहद जटिल विवादों को सुलझाती है। इन चुनौतियों का बखूबी सामना करने के लिए यह हाई कोर्ट हर तरह की तारीफ का हकदार है।"

CJI ने सिविल और कमर्शियल कानून (नागरिक और वाणिज्यिक न्यायशास्त्र) के क्षेत्र में दिल्ली हाई कोर्ट के योगदान खासकर विवादों को सुलझाने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में इसकी भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 2009 में इस हाई कोर्ट ने भारत का पहला 'हाईकोर्ट से जुड़ा मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया।

उन्होंने इसके ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन का भी जिक्र किया, जिसके तहत महत्वपूर्ण सिविल और कमर्शियल विवादों की सुनवाई सीधे हाईकोर्ट में हो सकती है, और पक्षकारों को पहले जिला अदालतों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

CJI ने हाईकोर्ट के विशेष इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इसने अपने कानूनी फैसलों की गुणवत्ता के लिए भारत और विदेशों में एक मजबूत पहचान बनाई।

इसके अलावा, जस्टिस कांत ने कहा कि आज अदालतों के सामने ऐसे सवाल आ रहे हैं, जिनके बारे में एक दशक पहले सोचना भी मुश्किल था जैसे कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा बनाई गई



किसी रचना पर कॉपीराइट का दावा किया जा सकता है? 'डीपफेक के मामले में कानून को कैसे कदम उठाने चाहिए? और तकनीक को व्यक्तिगत अधिकारों को नुकसान पहुँचाने से रोके बिना, नवाचार को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है उन्होंने आगे कहा कि ऐसे सवालों के जवाब शायद ही कभी कानून की किताबों में मिलते हैं, इसलिए अदालतों को संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ना पड़ता है।

CJI ने कहा, 'जहां कानून खामोश है, वहां संविधान ही हमारा मार्गदर्शन करता है। संविधान में दिए गए गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के वादे तकनीक के बदलने से नहीं बदलते, और हर नए सवाल का जवाब इसी नजरिए से दिया जाना चाहिए।"

उन्होंने भरोसा जताया कि दिल्ली हाईकोर्ट लोगों के अधिकारों और गरिमा का ध्यान रखते हुए सामने आ रही नई चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा।

उन्होंने कहा, "इस वादे पर मजबूती से कायम रहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट खुले दिमाग से नई चुनौतियों का सामना कर सकता है। बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाते हुए वे कभी भी उस व्यक्ति को नहीं भूलेंगे, जिसकी सुरक्षा के लिए यह अदालत बनी है।"

सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस विक्रम नाथ ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने पिछले छह दशकों में कानून के विकास और संस्थागत प्रगति में दिल्ली हाई कोर्ट के योगदान की तारीफ की।

हल्के-फुल्के अंदाज में जस्टिस नाथ ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज कभी-कभी 'सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी ज्यादा ताकतवर' लगते हैं।

उन्होंने कहा, 'इस अदालत के जजों का एक अलग ही प्रभाव होता है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने आप में सम्मान और अधिकार पैदा करता है। मैंने देखा है कि जब वे सुप्रीम कोर्ट आते हैं, तब भी वे उसी आत्मविश्वास और गरिमा के साथ आते हैं।"

उन्होंने इसका कारण राष्ट्रीय राजधानी में बेहद महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला लेने के अनुभव को बताया।

जस्टिस नाथ ने दिल्ली हाईकोर्ट बार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि यहां से देश के कुछ बेहतरीन वकील निकले हैं और इस अदालत में वकालत का स्तर बहुत ऊंचा है।

उन्होंने कहा, "एक अच्छी तैयारी के साथ आया वकील कभी-कभी जज को भी अपनी राय पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। हमारे पेशे की यही बात मुझे हमेशा से पसंद रही है।"

इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज, हाईकोर्ट के मौजूदा जज और पूर्व जज भी शामिल हुए।

करोड़ों खर्च, फिर भी वीरान पड़ा कोइड़ा मिनी स्टेडियम

खनिज संपदा से समृद्ध क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की उपेक्षा; डीएमएफ फंड से निर्मित स्टेडियम बदहाली का शिकार



निर्माण पर भारी राशि खर्च होने के बावजूद खेल सुविधाएं नदारद, रखरखाव और उपयोगिता पर उठ रहे सवाल

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र कोइड़ा/सुंदरगढ़

खनिज संपदा से समृद्ध सुंदरगढ़ जिले के कोइड़ा क्षेत्र में विकास की चमक के बीच खेल प्रतिभाओं का भविष्य धुंधला दिखाई दे रहा है। युवाओं को खेल का बेहतर मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्मित मिनी स्टेडियम आज अपनी बदहाली और उपेक्षा की कहानी कह रहा है। जिस परिसर में खिलाड़ियों के कदमों की आहट, अभ्यास का उत्साह और भविष्य के सपनों की गूंज सुनाई देनी चाहिए थी, वहां वीरानी का दृश्य सार्वजनिक धन के उपयोग और विकास योजनाओं की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

प्राप्त समाचार के अनुसार, जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) निधि से इस स्टेडियम के निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए। वर्ष 2021-22 में शुरू हुई निर्माण संबंधी पहल का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को खेलकूद के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना था। लेकिन निर्माण के बाद भी यदि स्टेडियम नियमित खेल गतिविधियों का केंद्र नहीं बन पाया है, तो यह केवल एक भवन या मैदान की समस्या नहीं, बल्कि विकास की प्राथमिकताओं और क्रियान्वयन की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न है।

विडंबना देखिए—जिस क्षेत्र की धरती से खनिज संपदा निकलकर अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है, उसी क्षेत्र के युवाओं को खेल सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़े, तो विकास के दावों का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। खेल मैदान केवल मनोरंजन की जगह नहीं होते; वे अनुशासन, स्वास्थ्य, सामाजिक सहभागिता और युवाओं के भविष्य निर्माण के केंद्र होते हैं।

अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि स्टेडियम की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या निर्माण के बाद संचालन, रखरखाव और खेल गतिविधियों की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी? संबंधित विभाग को निर्माण लागत, कार्य की गुणवत्ता, हस्तांतरण, रखरखाव और वर्तमान उपयोग की स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए।

जनधन से बने ढांचे का वास्तविक मूल्य उसके निर्माण में नहीं, बल्कि जनता को मिलने वाले लाभ में है। यदि करोड़ों की लागत से तैयार स्टेडियम खिलाड़ियों के काम नहीं आ रहा, तो यह व्यवस्था के लिए आत्ममंथन का विषय है। कोइड़ा के युवाओं को केवल स्टेडियम की इमारत नहीं, बल्कि उसमें खेलते हुए अपने सपनों को साकार करने का अवसर चाहिए।

खनिज संपदा से मालामाल सुंदरगढ़, फिर भी जनसुविधाओं का अकाल!

DMF की हजारों करोड़ की राशि पर उठे गंभीर सवाल, खनन प्रभावित गांवों में बुनियादी सुविधाएं बदहाल; जनता के हक का पैसा आखिर कहां हो रहा खर्च?

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र सुंदरगढ़।

लौह अयस्क और कोयले की अकूत संपदा से देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला सुंदरगढ़ आज एक ऐसे विरोधाभास का सामना कर रहा है, जहां खनिज संपदा से सरकारी खजाना तो लगातार भर रहा है, लेकिन खनन प्रभावित क्षेत्रों के आम नागरिक अब भी पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) की स्थापना का मूल उद्देश्य खनन से प्रभावित लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना था, लेकिन इसके क्रियान्वयन और खर्च की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल



खड़े हो रहे हैं।

आंकड़ों पर गौर करें तो लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा 30 जुलाई 2025 को प्रस्तुत जानकारी के अनुसार सुंदरगढ़ में वित्तीय वर्ष 2023-24 में DMF के तहत 1,518.27 करोड़ रुपये और 2024-25 में 1,620.38 करोड़ रुपये जमा हुए। यानी इन दो वर्षों में ही 3,138.65 करोड़ रुपये का योगदान इस कोष में आया। यह राशि अपने आप में जिले के समग्र विकास की तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है।

लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट ने इस व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार सुंदरगढ़ में हॉकी स्टेडियम निर्माण पर DMF से 136.77 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि यह परियोजना निर्धारित PMKKKY दिशानिर्देशों के तहत अनुमन्य गतिविधियों में शामिल नहीं थी। इसी तरह 2021 से 2023 के बीच श्रमिकों को PPE किट उपलब्ध कराने के नाम पर 59.13 करोड़ रुपये के व्यय पर भी ऑडिट ने सवाल उठाए हैं।

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि जिस जनता के नाम पर यह धनराशि एकत्रित होती है, उसी जनता को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा। खनन प्रभावित बस्तियों में धूल, प्रदूषण, क्षतिग्रस्त सड़कें, दूषित जल और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आज भी गंभीर चुनौती बनी हुई हैं।

अब जिला प्रशासन और DMF प्रबंधन से यह सवाल पूछना जरूरी है कि करोड़ों-अरबों की राशि का वास्तविक लाभ किन गांवों और परिवारों तक पहुंचा? परियोजनाओं की प्राथमिकता किसने तय की और उनके परिणामों का स्वतंत्र मूल्यांकन कब हुआ? जनता के हक का यह कोष केवल निर्माण कार्यों और कागजी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके प्रत्येक रुपये का हिसाब सार्वजनिक हो और खर्च की प्राथमिकता खनन प्रभावित नागरिकों की जरूरतें बनें।

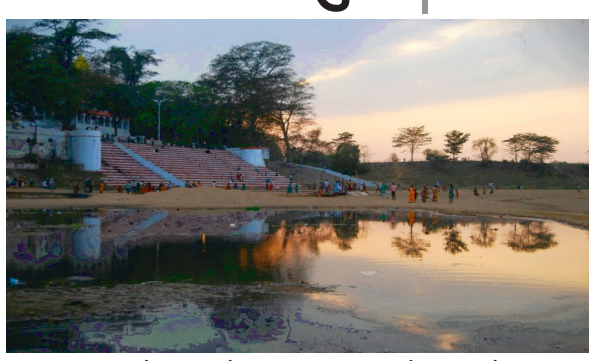
वेदव्यास में ब्राह्मणी नदी पर बनेगा 390 मीटर लंबा भव्य पुल

14 नवंबर को होगा भूमिपूजन, पर्यटन विकास को मिलेगी नई पहचान; राज्यसभा सांसद दिलीप राय के निरंतर प्रयासों से परियोजना को मिली गति

ऋषिकेश राय कॉलेज में प्रख्यात समाजसेवी की आदमकद प्रतिमा का भी होगा अनावरण

रिपोर्ट डा राजकुमार यादव परिवहन विशेष समाचार पत्र राउरकेला

औद्योगिक नगरी राउरकेला के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन मानचित्र पर वेदव्यास की पहचान को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल आकार लेने जा रही है। ब्राह्मणी नदी के त्रिवेणी संगम पर 390 मीटर लंबे आधुनिक आरसीसी पुल के निर्माण तथा नदी तट के सौंदर्यीकरण की महत्वाकांक्षी परियोजना का भूमिपूजन आगामी 14 नवंबर को प्रस्तावित है। इसे केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय पर्यटन, आधारभूत संरचना और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को विस्तार देने वाली महत्वपूर्ण सौगात के रूप में देखा जा रहा है।



इस कार्यक्रम में ओडिशा के लोक निर्माण मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय तथा विधानसभा उपाध्यक्ष भवानी भोई के शामिल होने की जानकारी दी गई है।

इस परियोजना को धरातल पर लाने में राज्यसभा सांसद दिलीप राय के निरंतर प्रयासों और सक्रिय पहल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उन्होंने अपने स्तर पर लगातार प्रयास किए और संबंधित स्तरों पर इस विषय को मजबूती से उठाया। उनके इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वेदव्यास को आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में यह परियोजना आगे बढ़ सकी है।

वेदव्यास मंदिर के निकट प्रस्तावित पुल पानपोष और छेंड क्षेत्र को जोड़ेगा। अंग्रेजी अक्षर 'एस' की आकृति में तैयार होने वाला यह 10 मीटर चौड़ा पुल चार मीटर के साइकिल ट्रैक और दोनों ओर 2.5-2.5 मीटर के पैदल पथ से सुसज्जित होगा। परियोजना में 170 मीटर लंबी रिटेनिंग वॉल, पार्किंग, शौचालय,



प्रकाश व्यवस्था, खाद्य कियोस्क, बैठने की सुविधा, मूर्तियां और हरित क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे। अक्टूबर 2028 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है।

इससे स्थानीय पर्यटन, रोजगार और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलने की संभावनाएं हैं। साथ ही 14 नवंबर को ऋषिकेश राय कॉलेज में प्रख्यात समाजसेवी ऋषिकेश राय की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी प्रस्तावित है। इस प्रकार यह दिन वेदव्यास के विकास और क्षेत्र की सामाजिक विरासत, दोनों के लिए महत्वपूर्ण अवसर बनने जा रहा है।

रन फॉर यूनिटी मैराथन में दौड़े जिलावासी



रन फॉर यूनिटी मैराथन में दौड़े जिलावासी

परिवहन विशेष न्यूज

खूंटी। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत आज बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, खूंटी से 'Run for Unity Marathon' का आयोजन किया गया। उपायुक्त मो० जावेद हुसैन एवं पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। इस दौरान 5 किलोमीटर पुरुष वर्ग तथा 2.5 किलोमीटर महिला एवं बच्चों की दौड़ आयोजित की गई। उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त सहित, गोपनीय प्रभारी, कार्यपालक पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी अन्य पदाधिकारियों ने भी दौड़ में शामिल होकर एकता, आपसी सद्भाव एवं स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया।

मैराथन के पुरुष वर्ग की 5 किलोमीटर दौड़ में अमन शमद ने प्रथम, मोहन होरो ने द्वितीय तथा तरुण कच्छप ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, महिला वर्ग की 2.5 किलोमीटर दौड़ में संगीता मरांडी ने प्रथम, मरियम भेंगरा ने द्वितीय तथा पेरोनिका सोरेन ने तृतीय स्थान हासिल किया। सभी विजेता प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित कर ट्रॉफी एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर उपायुक्त मो० जावेद हुसैन ने जिलावासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खेल एवं शारीरिक गतिविधियों को प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। इस मैराथन का उद्देश्य केवल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी को नियमित रूप से किसी न किसी शारीरिक गतिविधि से जुड़ने के लिए प्रेरित करना भी है। उन्होंने नशे की बुरी आदतों के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नशा व्यक्ति के जीवन के साथ-साथ उसके परिवार को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। हम सभी को नशामुक्ति के संकल्प को अपने जीवन में उतारना चाहिए तथा अपने भाई-बहनों एवं परिवार के अन्य सदस्यों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने आगे भी इस प्रकार के आयोजन कर लोगों को जागरूक कर जनभागीदारी और बढ़ाने की बात कही। अंत में उन्होंने आयोजन को सफल बनाने में सहभागी सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया।

वहीं, पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने कहा कि 'Run for Unity Marathon' जैसे आयोजन समाज में एकता, अनुशासन एवं स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के साथ युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि खूंटी जिले में खेल के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यहां के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है।

परिवहन मेले का मंडलायुक्त ने रिबन काटकर किया शुभारंभ

रिपोर्ट विशेष संवाददाता परिवहन विशेष समाचार पत्र

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा - जीवन रक्षा के संकल्प के साथ आज दिनांक 31 अक्टूबर 2026, शनिवार को संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) परिसर, सहारनपुर में परिवहन मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि मण्डलायुक्त श्री रूपेश कुमार द्वारा किया गया

इस अवसर पर मण्डलायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप परिवहन विभाग की सभी सेवाओं को एक ही छत के नीचे आमजन तक पहुँचाना इस मेले का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने बकाया कर, फिटनेस, परमिट व अन्य लंबित कार्यों का समयबद्ध निस्तारण कराएं।परिवहन मेले में विभाग द्वारा विशेष काउंटरों की व्यवस्था की गई है। बकाया वसूली एवं शास्ति छूट काउंटर पर नियम-24, उ.प्र. मोटर यान कराधान नियमावली-1998 के अंतर्गत बकाया कर पर शास्ति (पेनल्टी) में छूट का लाभ देते हुए ऑनलाइन (UPI/POS) व नकद कर जमा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।इसी प्रकार नया पंजीयन काउंटर पर नए वाहनों के क्रय, बीमा, वित्तपोषण एवं तत्काल पंजीयन तथा अनुबंध की एकीकृत व्यवस्था, फिटनेस एवं परमिट



काउंटर पर समस्त फिटनेस व परमिट के नवीनीकरण और नए परमिट आवेदन की सुविधा, स्क्रैपेज काउंटर पर पुराने/स्क्रैप वाहनों के CoD प्रमाण-पत्र के आधार पर नए वाहनों के तत्काल पंजीयन व नियमानुसार छूट की सुविधा तथा नागरिक सहायता काउंटर पर आरटीओ में मोबाइल नंबर अपडेट, PUCC से संबंधित OTP समस्या का समाधान, 01-04-2019 से पूर्व के वाहनों में HSRP लगवाने, स्वामित्वांतरण, वाहन निरस्तीकरण एवं ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी ऑनलाइन सहायता प्रदान की जा रही है।कार्यक्रम में आरटीओ शंकर जी सिंह, एआरटीओ मानवेंद्र प्रताप सिंह, आर आई रोहित कुमार सिंह व संभागीय परिवहन अधिकारी सहित विभाग के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, वाहन स्वामी, ट्रांसपोर्टर्स एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। परिवहन विभाग, सहारनपुर ने सभी से मेले में प्रतिभाग कर विभागीय सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की है।

परिवहन मेले में उमड़े वाहन स्वामी, एक ही दिन में 52.78 लाख रुपये का राजस्व जुटाया

परिवहन विशेष न्यूज

सहारनपुर। वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्टरों को परिवहन विभाग से जुड़ी विभिन्न सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने तथा विभागीय राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से शनिवार को सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, सहारनपुर में परिवहन मेले का आयोजन किया गया। परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर आयोजित इस मेले का उद्घाटन सहारनपुर मंडल के मंडलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार ने किया। मेले में बड़ी संख्या में वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्टरों ने पहुंचकर परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए आवेदन किए। मेले के दौरान विभाग को 52.78 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि 178 वाहन स्वामियों के आवेदन प्राप्त किए गए।

परिवहन मेले के उद्घाटन अवसर पर मंडलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार ने विभाग की ओर से लगाए गए विभिन्न काउंटरों का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से मेले में आने वाले वाहन स्वामियों को दी जा रही सेवाओं और उनके आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। मंडलायुक्त ने परिवहन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जनहित और राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से समय-समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। ऐसे आयोजनों से जनपद के वाहन स्वामियों को एक ही स्थान पर विभिन्न सुविधाएं मिलती हैं और उन्हें अपने कार्यों के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से विभागीय कार्यों में तेजी आने के साथ-साथ राजस्व प्राप्ति में भी वृद्धि होती है।

मेले में परिवहन विभाग की ओर से वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए अलग-अलग काउंटर स्थापित किए गए थे, जहां परिवहन संबंधी कार्यों के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, मेले में कुल 178 वाहन स्वामियों ने विभिन्न कार्यों के लिए आवेदन किया, जिनसे विभाग को 52.78 लाख रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त वाहन पोर्टल पर मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए 312 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि सारथी पोर्टल पर मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए 152 लोगों ने आवेदन किया। इस प्रकार मोबाइल नंबर अपडेट कराने से संबंधित कुल 464 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा त्वरित निस्तारण किया गया।

परिवहन विभाग की इस पहल से उन वाहन स्वामियों को विशेष सुविधा मिली, जिन्हें अपने वाहनों से संबंधित कार्यों, पोर्टल पर मोबाइल नंबर अपडेट कराने और अन्य परिवहन संबंधी प्रक्रियाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक ही स्थान पर विभिन्न काउंटरों के माध्यम से आवेदन प्राप्त होने और उनका शीघ्र निस्तारण किए जाने से लोगों को राहत मिली। अधिकारियों का कहना था कि ऐसे मेलों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विभागीय सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और जनसुलभ बनाना है, ताकि आम वाहन स्वामी और ट्रांसपोर्टर बिना अनावश्यक परेशानी के अपने कार्य पूरे करा सकें।

इस अवसर पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) शंकर जी. सिंह ने वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्टरों से अपील की कि वे परिवहन विभाग की ओर से आयोजित किए जा रहे इन मेलों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने जानकारी दी कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार सहारनपुर स्थित सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में आगामी 27 नवंबर 2026 और 26 दिसंबर 2026 को भी परिवहन मेले आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो वाहन स्वामी और ट्रांसपोर्टर किसी कारणवश 31 अक्टूबर को आयोजित मेले में नहीं पहुंच सके, वे निर्धारित तिथियों पर कार्यालय पहुंचकर परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। परिवहन मेले के दौरान सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) मानवेन्द्र प्रताप सिंह, सम्भागीय मोटर वाहन निरीक्षक रोहित कुमार सिंह तथा कार्यालय के प्रवर्तन अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा जनपद के प्रमुख ट्रांसपोर्टरों में रजनीश चन्दा, पी.पी. सिंह, ललित पोपली, रोबिन मोगा, पंकज और मनोज वर्मा सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे।

डॉक्टर बनने का सपना, लंबी ट्रेनिंग और पारिवारिक जीवन की अनदेखी कीमत





● डॉ. विजय गर्ग

पुरुष डॉक्टरों को भी पारिवारिक अपेक्षाओं और सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता है। जब उनके मित्र और अन्य पेशों के साथी कमाना शुरू कर देते हैं, तब वे परीक्षाओं, फीस, हॉस्टल और प्रशिक्षण की व्यस्तताओं में उलझे रह सकते हैं। माता-पिता की बढ़ती उम्र, परिवार की आर्थिक जरूरतें और विवाह की जिम्मेदारियाँ तनाव बढ़ा सकती हैं। यदि अनिवार्य सेवा के लिए दूरदराज के क्षेत्र में नियुक्ति हो जाए, तो जीवनसाथी के साथ रहना और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना कठिन हो सकता है।

भारत में डॉक्टर बनना केवल एक पेशा चुनना नहीं, बल्कि वर्षों की कठिन पढ़ाई, आर्थिक दबाव, मानसिक तनाव और व्यक्तिगत त्याग से भरी लंबी यात्रा शुरू करना है। चिकित्सा का पेशा निस्संदेह सम्मानजनक और मानव सेवा का उत्कृष्ट माध्यम है, लेकिन इस सफर की वास्तविक चुनौतियों को समझे बिना मेडिकल शिक्षा में प्रवेश लेना विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी भूल साबित हो सकता है।

आज लाखों विद्यार्थी नीट की तैयारी करते हैं। कई विद्यार्थी दो या तीन वर्ष कोचिंग में बिताते हैं, फिर एमबीबीएस में प्रवेश पाते हैं। इसके बाद इंटर्नशिप, स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा, एमडी/एमएस, सुपर-स्पेशियलिटी की पढ़ाई और विभिन्न राज्यों में अनिवार्य सेवा बांड जैसी जिम्मेदारियाँ सामने आती हैं। सवाल यह है कि क्या डॉक्टर तैयार करने की इस व्यवस्था में उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के लिए पर्याप्त स्थान है?

डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है?

एक विद्यार्थी की यात्रा का अनुमानित खाका इस प्रकार हो सकता है:

- 17–18 वर्ष: नीट युजी की तैयारी और MBBS में प्रवेश।
- 17.5–23 वर्ष: एमबीबीएस की साढ़े पाँच वर्ष की अवधि, जिसमें इंटर्नशिप शामिल है।
- 23–24 वर्ष: नीट -पीजीकी तैयारी, प्रवेश की प्रतीक्षा या अन्य सेवा संबंधी जिम्मेदारियाँ।
- 24–27 वर्ष: एमडी/एमएस की तीन वर्ष की पढ़ाई।
- 27–28 वर्ष: सीनियर रेजिडेंसी, सेवा बांड या सुपर-स्पेशियलिटी प्रवेश की तैयारी।
- 28–31 वर्ष: डीएम/एमसीएचजैसी सुपर-स्पेशियलिटी की लगभग तीन वर्ष की ट्रेनिंग।
- इसके बाद: संबंधित राज्य और पाठ्यक्रम के नियमों के अनुसार अतिरिक्त सेवा बांड या अन्य दायित्व।

यह समय-सारणी प्रत्येक डॉक्टर पर समान रूप से लागू नहीं होती। अनेक विद्यार्थी सीधे एमबीबीएस के बाद काम शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ एमडी/एमएच के बाद विशेषज्ञ बनकर स्वतंत्र पेशेवर जीवन शुरू करते हैं। फिर भी, सुपर-स्पेशलिस्ट बनने की यात्रा अक्सर तीस वर्ष की उम्र पार कर जाती है।

इसकी तुलना में दूसरे क्षेत्रों के अनेक स्नातक 21–23 वर्ष की उम्र में नौकरी शुरू कर देते हैं और अपने परिवार तथा आर्थिक भविष्य की योजना बनाने लगते हैं। चिकित्सा के विद्यार्थियों को भी ऐसा करने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन लंबी ट्रेनिंग और अनिवार्य सेवाओं के कारण उनकी स्वतंत्रता अक्सर देर से आती है।

1. महिला डॉक्टरों के सामने विशेष चुनौतियाँ

महिला डॉक्टरों के लिए चिकित्सा शिक्षा की लंबी अवधि कई बार अतिरिक्त सामाजिक और जैविक चुनौतियाँ पैदा करती है। पढ़ाई, परीक्षाओं, रेजिडेंसी और सेवा बांड के बीच विवाह, मातृत्व तथा परिवार की योजना बनाना कठिन हो सकता है।

गर्भधारण की संभावना और उससे जुड़े जोखिम उम्र के साथ बदलते हैं। विशेष रूप से 35 वर्ष के बाद कुछ गर्भावस्था संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं, हालाँकि हर महिला की स्थिति अलग होती है। इसलिए महिला डॉक्टरों को अपने निजी जीवन के निर्णय लेने के लिए उचित समय, सुरक्षित कार्यस्थल और सहायक नीतियाँ मिलनी चाहिए।

यह मुद्दा केवल व्यक्तिगत सुविधा का नहीं, बल्कि समान अवसर, गरिमा और लैंगिक न्याय का भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 से जुड़े समानता, भेदभाव-विरोधी संरक्षण तथा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत इस बहस को महत्वपूर्ण बनाते हैं। हालाँकि किसी विशेष सेवा बांड को स्वतः असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता; उसकी वैधता संबंधित कानून, परिस्थितियों और न्यायिक व्याख्या पर निर्भर करती है।

2. पुरुष डॉक्टरों पर सामाजिक और आर्थिक दबाव

पुरुष डॉक्टरों को भी पारिवारिक अपेक्षाओं और सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता है। जब उनके मित्र और अन्य पेशों के साथी कमाना शुरू कर देते हैं, तब वे परीक्षाओं, फीस, हॉस्टल और प्रशिक्षण की व्यस्तताओं में उलझे रह सकते हैं।

माता-पिता की बढ़ती उम्र, परिवार की आर्थिक जरूरतें और विवाह की जिम्मेदारियाँ तनाव बढ़ा सकती हैं। यदि अनिवार्य सेवा के लिए दूरदराज के क्षेत्र में नियुक्ति हो जाए, तो जीवनसाथी के साथ रहना और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना कठिन हो सकता है।

डॉक्टर बनने में लगने वाला समय अपने आप में समस्या नहीं है; समस्या तब पैदा होती है जब प्रशिक्षण और सेवा की व्यवस्था व्यक्ति की वास्तविक पारिवारिक जरूरतों की अनदेखी करती है।

3. ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर आवास की समस्या

ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की नियुक्ति स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए आवश्यक है। लेकिन केवल नियुक्ति कर देना पर्याप्त नहीं है। डॉक्टरों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, शौचालय, रसोई और आवश्यक सुविधाएँ भी मिलनी चाहिए।

जहाँ डॉक्टरों के लिए परिवार सहित रहने की व्यवस्था नहीं होती, वहाँ विवाहित डॉक्टरों और छोटे बच्चों वाले परिवारों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं की सुरक्षा, परिवहन और आपातकालीन सहायता भी महत्वपूर्ण हैं।

यदि सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना चाहती है, तो उसे डॉक्टरों के लिए सम्मानजनक जीवन-परिस्थितियाँ सुनिश्चित करनी होंगी। अच्छी सुविधाएँ और प्रोत्साहन ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक डॉक्टरों को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

4. मानसिक स्वास्थ्य और बर्नआउट का संकट

लगातार परीक्षाएँ, प्रतिस्पर्धा, लंबी ड्यूटी, नींद की कमी और मरीजों की गंभीर जिम्मेदारियाँ चिकित्सा विद्यार्थियों तथा रेजिडेंट डॉक्टरों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं।

कुछ प्रशिक्षण व्यवस्थाओं में अत्यधिक लंबे कार्य-घंटे, अपर्याप्त विश्राम और परिवार से दूरी तनाव को और बढ़ा देते हैं। इसके परिणामस्वरूप थकान, चिंता, अवसाद और बर्नआउट का खतरा बढ़ सकता है।

डॉक्टरों से दूसरों की जान बचाने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उनकी अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। संस्थानों को पर्याप्त स्टाफ, उचित ड्यूटी-रोस्टर, नियमित विश्राम, गोपनीय मानसिक स्वास्थ्य सहायता और शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था करनी चाहिए।

5. सेवा बांड: जनहित और डॉक्टरों के अधिकारों में संतुलन

सरकार का तर्क है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सस्ती शिक्षा प्राप्त करने वाले डॉक्टर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा दें, ताकि आम नागरिकों को चिकित्सा सुविधाएँ मिल सकें। यह उद्देश्य उचित और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

लेकिन सेवा बांड तभी प्रभावी होगा जब उसकी शर्तें पारदर्शी, उचित और व्यावहारिक हों। बांड की अवधि, नियुक्ति का स्थान, कार्य-परिस्थितियाँ, वेतन, आवास और पारिवारिक कठिनाइयों के समाधान के बारे में स्पष्ट नियम होने चाहिए।

जहाँ संभव हो, ग्रामीण सेवा के लिए उचित वेतन, आवास भत्ता, सुरक्षित कार्यस्थल, अतिरिक्त प्रशिक्षण के अवसर और भविष्य की नियुक्तियों में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। गंभीर पारिवारिक या चिकित्सकीय परिस्थितियों में निष्पक्ष छूट अथवा वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार होना चाहिए।

डॉक्टरों को केवल दंड के भय से ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने के बजाय ऐसी परिस्थितियाँ तैयार करनी चाहिए, जिनमें वे स्वेच्छा से सेवा करना चाहें।

6. मेडिकल में प्रवेश से पहले विद्यार्थियों और अभिभावकों को क्या सोचना चाहिए?

मेडिकल शिक्षा में प्रवेश लेने से पहले केवल डॉक्टर के सामाजिक सम्मान या संभावित आय को देखकर निर्णय न लें। विद्यार्थी अपनी रुचि, धैर्य, मानसिक तैयारी और आर्थिक स्थिति का आकलन करें।

अभिभावकों को भी समझना चाहिए कि डॉक्टर बनने की यात्रा लंबी है और इसमें कई वर्षों तक नियमित आय सीमित रह सकती है। MBBS के बाद विशेषज्ञता करना एक विकल्प है, अनिवार्यता नहीं। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

प्रवेश से पहले संबंधित कॉलेज की फीस, छात्रवृत्ति, हॉस्टल, इंटर्नशिप, सेवा बांड, स्नातकोत्तर प्रवेश की संभावनाओं और नौकरी के विकल्पों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।

निष्कर्ष: डॉक्टर भी इंसान हैं

भारत को अच्छे डॉक्टरों की आवश्यकता है, लेकिन अच्छे डॉक्टर तैयार करने के लिए ऐसी व्यवस्था भी चाहिए जो उनके जीवन, स्वास्थ्य और परिवार का सम्मान करे। चिकित्सा शिक्षा में कठोर परिश्रम और लंबा प्रशिक्षण आवश्यक हो सकता है, परंतु अनावश्यक देरी, असुरक्षित आवास, अत्यधिक कार्यभार और असंगत सेवा शर्तों को सुधारना भी उतना ही जरूरी है।

मेडिकल में प्रवेश लेने से पहले ठहरिए, सोचिए और समझिए। यह किसी विद्यार्थी को डॉक्टर बनने से रोकने की अपील नहीं, बल्कि उसे पूरी जानकारी के साथ निर्णय लेने की सलाह है।

डॉक्टर बनना मानवता की सेवा का महान अवसर है। लेकिन सेवा का अर्थ अपने जीवन और परिवार की हर जरूरत का त्याग करना नहीं होना चाहिए। एक संवेदनशील स्वास्थ्य व्यवस्था वही है जो मरीजों की देखभाल करने वाले डॉक्टरों की देखभाल भी करती है।

सेवानिवृत्त प्राचार्य / शैक्षिक स्तंभकार / प्रख्यात वैज्ञानिक
स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर. मलोट, पंजाब – 152107

आंकड़ों से परे: भारत में गरीबी में कमी की वास्तविक तस्वीर – विश्व बैंक की रिपोर्ट

डॉ. विजय गर्ग



गरीबी किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण मापदंड है। यह केवल लोगों की आय को ही नहीं दर्शाती, बल्कि भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आवास, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुंच को भी प्रतिबिंबित करती है। गरीबी कम करने के क्षेत्र में भारत की प्रगति ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। विश्व बैंक की हालिया रिपोर्टें जीवन स्तर में हुए महत्वपूर्ण सुधारों को उजागर करती हैं, लेकिन साथ ही यह भी बताती हैं कि अभी कई चुनौतियां बाकी हैं।

विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की गरीबी एवं समानता संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए निर्धारित 4.20 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की गरीबी रेखा के आधार पर भारत में गरीबी की दर 2011-12 में 57.7 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में घटकर 16.1 प्रतिशत रह गई। इसका अर्थ है कि लगभग 49.6 करोड़ लोग इस गरीबी रेखा से ऊपर आ गए।

रिपोर्ट में अत्यधिक गरीबी में आई उल्लेखनीय कमी का भी उल्लेख किया गया है। प्रतिदिन 3 अमेरिकी डॉलर से कम आय पर जीवनयापन करने वाले लोगों का अनुपात 2011-12 में 27.1 प्रतिशत था, जो 2023-24 में घटकर 2.6 प्रतिशत रह गया। ये आंकड़े परिवारों की खपत और जीवन स्थितियों में आए महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं।

विश्व बैंक ने यह भी अनुमान लगाया है कि 4.20 डॉलर वाली गरीबी रेखा के आधार पर भारत में गरीबी की दर 2026 में अनुमानित 14.2 प्रतिशत से घटकर 2028 तक 12.1 प्रतिशत हो सकती है। यह दो वर्षों का अनुमान है, न कि बारह वर्षों का। इसकी प्राप्ति आर्थिक परिस्थितियों और रोजगार बाजार में होने वाले बदलावों पर भी निर्भर करेगी।

गरीबी में कमी के पीछे क्या कारण हैं?

इस प्रगति के पीछे कई महत्वपूर्ण कारक हैं। आर्थिक विकास, परिवारों की बढ़ती खपत, रोजगार के अवसर और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

खाद्य सुरक्षा योजनाओं और रियायती दरों पर अनाज वितरण ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपनी बुनियादी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता दी है। सामाजिक सहायता योजनाओं और आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच ने भी परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने में योगदान दिया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव रोजगार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। 2017 से 2023 के बीच भारत में रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या में लगभग 13.4 करोड़ की वृद्धि हुई। ग्रामीण महिलाओं का वेतनभोगी कार्यों में शामिल होना इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। जब परिवार के अधिक सदस्य कमाने लगते हैं, तो घरेलू आय बढ़ती है और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बल मिलता है।

ग्रामीण और शहरी गरीबी में अंतर

समग्र प्रगति के बावजूद भारत में गरीबी की स्थिति सभी क्षेत्रों में समान नहीं है। 4.20 डॉलर की गरीबी रेखा के आधार पर 2023 में ग्रामीण गरीबी की दर लगभग 19.3 प्रतिशत थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 8.6 प्रतिशत थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, स्थायी रोजगार और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। क्षेत्रीय असमानता भी एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक के कई राज्यों में गरीब आबादी का बड़ा हिस्सा रहता है।

इन असमानताओं को कम करने के लिए क्षेत्र-विशेष विकास योजनाओं, बेहतर बुनियादी ढांचे, कृषि के आधुनिकीकरण, ग्रामीण उद्योगों और शिक्षा के अधिक अवसरों की आवश्यकता है।

रोजगार और आय की चुनौती

विश्व बैंक के निष्कर्षों से एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है कि केवल रोजगार में वृद्धि आर्थिक सुरक्षा की गारंटी नहीं देती। रोजगार के अवसर बढ़ने के बावजूद वास्तविक आय में वृद्धि काफी सीमित रही है। नए रोजगारों में से कई कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में पैदा हुए हैं।

युवाओं में बेरोजगारी भी चिंता का विषय है। 2025-26 और 2026-27 की पहली तिमाहियों के बीच युवा बेरोजगारी की दर 14.6 प्रतिशत से बढ़कर 15.9 प्रतिशत होने की रिपोर्ट इस बात की आवश्यकता बताती है कि युवाओं और ग्रामीण महिलाओं के लिए अधिक प्रभावी रोजगार नीतियां बनाई जाएं।

भारत को उत्पादक, सुरक्षित और उचित वेतन वाले रोजगार पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए। कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा, स्वरोजगार, औद्योगिक विकास, आधुनिक कृषि और डिजिटल उद्योग युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर सकते हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं: प्रगति की नींव

गरीबी का स्थायी उन्मूलन केवल आर्थिक सहायता पर निर्भर नहीं हो सकता। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को अच्छे स्कूलों, डिजिटल शिक्षा, छात्रवृत्तियों और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी प्रतिभा विकसित करने के अवसर मिलने चाहिए।

इसी प्रकार, स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच परिवारों को महंगे इलाज के कारण गरीबी में जाने से बचा सकती है। बेहतर पोषण, स्वच्छता, साफ पेयजल और बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य सेवाएं मानव विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं।

आंकड़ों से परे: आगे का रास्ता

गरीबी के आंकड़े महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन वे मानवीय कठिनाइयों के हर पहलू को व्यक्त नहीं कर सकते। कोई परिवार अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से ऊपर आने के बावजूद खराब आवास, कुपोषण, अस्थिर रोजगार या बढ़ती महंगाई से जूझ सकता है।

विश्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि गरीबी के अनुमानों में बदलाव बेहतर मापन प्रणाली और जीवन स्तर में वास्तविक सुधार, दोनों कारणों से हो सकता है। इसलिए गरीबी के आंकड़ों को समझदारी और सावधानी से देखने की आवश्यकता है।

भारत के सामने अगली बड़ी चुनौती गरीबी में कमी को स्थायी समृद्धि में बदलना है। आर्थिक विकास का लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक बेहतर अवसरों, उचित मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सेवाओं तक समान पहुंच के माध्यम से पहुंचना चाहिए।

अंततः किसी विकासशील देश की सफलता केवल उसकी आर्थिक वृद्धि या गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले लोगों की संख्या से नहीं मापी जानी चाहिए। इसका वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि क्या प्रत्येक नागरिक सम्मान के साथ जीवन जी सकता है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सकता है और सार्थक रोजगार पा सकता है।

विश्व बैंक के निष्कर्ष भारत की प्रगति की एक उत्साहजनक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एक समावेशी और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। आंकड़ों से परे वास्तविक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ आम लोगों के दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल। शिक्षाविद्। प्रसिद्ध गणितज्ञ
अकादमिक संपादक, ऑनलाइन पत्रिका FNBWorld.com
स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर., मलोट, पंजाब – 152107

जीवन रक्षा का चमत्कार: न्यूजीलैंड की ब्लैक रॉबिन बनी 2026 की 'बर्ड ऑफ द ईयर'

डॉ. विजय गर्ग

न्यूजीलैंड की ब्लैक रॉबिन चिड़िया की कहानी इस बात का प्रेरणादायक उदाहरण है कि मानवीय दृढ़ संकल्प, वैज्ञानिक अनुसंधान और वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों से किसी प्रजाति को विलुप्त होने के कगार से वापस लाया जा सकता है। एक समय इस दुर्लभ चिड़िया की संख्या घटकर केवल पाँच रह गई थी। आज इसकी आबादी बढ़कर लगभग 350 बताई जाती है। वर्ष 2026 के लिए इसे 'बर्ड ऑफ द ईयर' घोषित किया जाना न केवल इस पक्षी की उपलब्धि है, बल्कि इसके संरक्षण के लिए किए गए असाधारण प्रयासों का सम्मान भी है।

विलुप्त होने के कगार पर पहुँची चिड़िया

ब्लैक रॉबिन का वैज्ञानिक नाम Petroica traversi है। यह न्यूजीलैंड के चैथम द्वीप समूह में पाई जाने वाली छोटी, गहरे रंग की चिड़िया है। इसका प्राकृतिक आवास सीमित है। बाहरी क्षेत्रों से आए शिकारी जीवों, प्राकृतिक आवास के विनाश और इसकी कम आबादी ने इसके अस्तित्व के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया था।

1980 के दशक में इसकी स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई थी। इसकी कुल संख्या केवल पाँच रह गई थी, जिनमें प्रजनन करने वाली केवल एक मादा ज्ञात थी। इतनी कम संख्या में किसी बीमारी, प्राकृतिक आपदा या प्रजनन में विफलता के कारण यह प्रजाति हमेशा के लिए समाप्त हो सकती थी।

लेकिन वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञों ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस प्रजाति को बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया।

विज्ञान और मानवीय समर्पण की जीत

ब्लैक रॉबिन को बचाने के लिए विशेषज्ञों ने एक व्यापक संरक्षण कार्यक्रम तैयार किया। इसके प्राकृतिक आवास की रक्षा की गई, शिकारी जीवों को नियंत्रित किया गया, घोंसलों की निगरानी की गई और प्रजनन की प्रक्रिया को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित किया गया।

इस अभियान में 'क्रॉस-फॉस्टरिंग' नामक तकनीक भी महत्वपूर्ण रही। इस विधि में किसी अन्य उपयुक्त पक्षी प्रजाति के घोंसले में अंडे रखे जाते हैं, ताकि वे पक्षी उन अंडों को से सकें और उनसे निकलने वाले बच्चों की देखभाल कर सकें। इस तकनीक सहित अन्य संरक्षण उपायों ने ब्लैक रॉबिन के सफल प्रजनन और बच्चों के जीवित रहने की संभावनाएँ बढ़ाने में सहायता की।

इस पक्षी की वापसी साबित करती है कि यदि वैज्ञानिक योजना, निरंतर निगरानी और समर्पित प्रयास किए जाएँ, तो बहुत कम संख्या में बची किसी प्रजाति को भी नया जीवन दिया जा सकता है।

यह सफलता रातोंरात नहीं मिली। इसके पीछे वर्षों का वैज्ञानिक अनुसंधान, धैर्य, मेहनत और विशेषज्ञों, संरक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय समुदायों का सहयोग था।

'बर्ड ऑफ द ईयर' का महत्व

ब्लैक रॉबिन को वर्ष 2026 का 'बर्ड ऑफ द ईयर' चुने जाने की खबर ने संकटग्रस्त वन्यजीवों के संरक्षण की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस प्रकार की मान्यता लोगों को दुर्लभ प्रजातियों के बारे में जानने और प्रकृति में उनकी भूमिका समझने के लिए प्रेरित कर सकती है।

पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बीजों को फैलाते हैं, कीटों की संख्या नियंत्रित करते हैं और कुछ पौधों के परागण में सहायता करते हैं। पक्षियों की संख्या में गिरावट पर्यावरण में होने वाले बदलावों का संकेत भी हो सकती है।

ब्लैक रॉबिन की कहानी हमें यह समझाती है कि जैव विविधता की रक्षा केवल दूर-दराज के जंगलों या द्वीपों तक सीमित नहीं है। यह पृथ्वी पर जीवन की विविधता, प्राकृतिक संतुलन और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने की साझा जिम्मेदारी है।

दुनिया के लिए महत्वपूर्ण सबक

ब्लैक रॉबिन की वापसी से कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला, किसी प्रजाति की संख्या अत्यधिक कम होने से पहले ही संरक्षण के उपाय शुरू कर देने चाहिए। दूसरा, वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और लंबे समय तक निगरानी आवश्यक है। तीसरा, सरकारों, वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदायों को मिलकर काम करना चाहिए।

ये सबक भारत के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। गिद्धों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और कई संकटग्रस्त जलीय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्राकृतिक आवासों की रक्षा, वैज्ञानिक निगरानी, जन-जागरूकता और पर्यावरण संबंधी कानूनों का प्रभावी पालन आवश्यक है।

आशा की नई किरण

केवल पाँच पक्षियों से लगभग 350 तक पहुँचने का ब्लैक रॉबिन का सफर सिर्फ एक पक्षी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए आशा का संदेश है। मानवीय गतिविधियाँ किसी प्रजाति को विलुप्त होने के कगार पर पहुँचा सकती हैं, लेकिन मानवीय जिम्मेदारी और वैज्ञानिक नवाचार उसे फिर से जीवन भी दे सकते हैं। हालाँकि, ब्लैक रॉबिन अभी भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इसके सुरक्षित द्वीपीय आवास में उपलब्ध स्थान सीमित होता जा रहा है। इसलिए संरक्षण विशेषज्ञ इसके लिए किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर एक नई आबादी स्थापित करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं।

इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश सरल है—जब मनुष्य प्रकृति का सम्मान करता है, विज्ञान का सहारा लेता है और समय रहते कदम उठाता है, तो एक छोटी-सी चिड़िया भी पूरी दुनिया के लिए आशा का प्रतीक बन सकती है।

सेवानिवृत्त प्राचार्य। शैक्षिक स्तंभकार। प्रख्यात वैज्ञानिक
स्ट्रीट कौर चंद, एम.एच.आर. मलोट, पंजाब – 152107

ई-कचरा प्रबंधन एवं जागरूकता ऑनलाइन क्विज में 13 हजार 500 प्रतिभागियों को मिला डिजिटल प्रमाणपत्र

टीचर्स ऑफ बिहार की ओर से 'प्रकृति प्रहरी' अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की पहल।

परिवहन विशेष न्यूज

पटना। पर्यावरण संरक्षण एवं ई-कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से टीचर्स ऑफ बिहार के 'प्रकृति प्रहरी' अभियान के अंतर्गत आयोजित ई-कचरा प्रबंधन एवं जागरूकता ऑनलाइन क्विज–2026 को व्यापक जनसमर्थन मिला। 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजित इस ऑनलाइन क्विज में भाग लेने वाले लगभग 13 हजार 500 प्रतिभागियों को डिजिटल प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। इस पहल के माध्यम से शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं आम लोगों को ई-कचरे के उचित निस्तारण, पुनर्चक्रण तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया।

क्विज में कुल 20 प्रश्न शामिल थे, जिन्हें हल करने के लिए प्रतिभागियों को मात्र 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। प्रश्नोत्तरी पूरी करने के 30 मिनट बाद डिजिटल प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इससे प्रतिभागियों को प्रोत्साहन मिला और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को व्यापक स्तर पर पहुँचाने में मदद मिली।

टीचर्स ऑफ बिहार के संस्थापक शिव कुमार एवं टेक्निकल टीम लीडर ई. शिवेंद्र प्रकाश सुमन ने कहा कि डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग कर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। ई-कचरे का अनियंत्रित निस्तारण मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण का कारण बन सकता है। ऐसे में जागरूकता आधारित ऑनलाइन गतिविधियाँ लोगों को जिम्मेदार व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं।





प्रकृति प्रहरी अभियान के संयोजक अभिषेक कुमार एवं क्विज के निर्माता-सह-सहसंयोजक कुमार अभिषेक ने कहा कि इस क्विज का उद्देश्य केवल प्रतिभागियों की जानकारी परखना नहीं, बल्कि ई-कचरे के सुरक्षित संग्रहण, अधिकृत पुनर्चक्रण तथा वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के प्रति व्यावहारिक जागरूकता विकसित करना भी है। लगभग 13 हजार 500 प्रतिभागियों की सहभागिता अभियान के लिए उत्साहजनक उपलब्धि है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से पर्यावरण संरक्षण के संदेश को अपने विद्यालय, परिवार और समाज तक पहुँचाने की अपील की।

प्रदेश प्रवक्ता रंजेश कुमार एवं प्रदेश मीडिया संयोजक मृत्युंजय कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि टीचर्स ऑफ बिहार द्वारा संचालित 'प्रकृति प्रहरी' अभियान पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। ऑनलाइन क्विज जैसी गतिविधियों से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को सीखने के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता फैलाने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि ई-कचरे का उचित प्रबंधन आज की आवश्यकता है और इसके लिए जनभागीदारी बेहद महत्त्वपूर्ण है।

उन्होंने सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं पर्यावरण प्रेमियों से अपील की कि वे ऐसे जागरूकता अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाएँ तथा अपने डिजिटल प्रमाणपत्र को 'प्रकृति प्रहरी' अभियान के आधिकारिक फेसबुक समूह में साझा कर अन्य लोगों को भी प्रेरित करें।

टीचर्स ऑफ बिहार की यह पहल स्वच्छ, स्वस्थ एवं हरित पर्यावरण के निर्माण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अभियान का संदेश स्पष्ट है—ई-कचरे को सामान्य कचरे की तरह इधर-उधर न फेंकें, बल्कि उसका सुरक्षित संग्रहण एवं अधिकृत केंद्रों के माध्यम से उचित निस्तारण सुनिश्चित करें।

सरदार पटेल की जयंती पर तुगलकाबाद में आयोजित हुई एकता दौड़, युवाओं ने लिया बढ़-चढ़कर हिस्सा

पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में निकली एकता दौड़, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विनय सहस्त्रबुद्धि रहे मुख्य अतिथि

स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली



नई दिल्ली: सरदार पटेल के 151वीं जयंती के मौके पर दिल्ली के तुगलकाबाद में पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी के नेतृत्व में विवेक बिधूड़ी फाउंडेशन व शिव आसरा ट्रस्ट के द्वारा एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़-चढ़कर युवाओं ने हिस्सा लिया। दक्षिणी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए और एकता दौड़ में दौड़े। इस दौड़ को केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर एवं दिल्ली भाजपा प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धि ने झंडा दिखाकर शुरू किया।

मौजूद युवाओं और लोगों को संबोधित करते हुए रमेश बिधूड़ी ने कहा कि 2014 में सरदार पटेल की जयंती मनाने के लिए एकता दौड़ की शुरुआत की गई थी। तब से ही दक्षिणी दिल्ली में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सरदार पटेल ने आजादी के बाद देश को एक करने के लिए काम किया और अलग-अलग रियासतों में बंटे देश को एकजुट किया। उनके इस योगदान को याद करने और युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं और युवाओं का आभार व्यक्त किया।

इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर और विनय सहस्त्रबुद्धि ने भी देश के लिए सरदार पटेल के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि देश अलग-अलग रियासतों में बंटा था, जिसे एक करने का काम सरदार पटेल ने किया। उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। युवा पीढ़ी को उनके योगदान से परिचित कराने के उद्देश्य से एकता दौड़ का आयोजन किया गया।

इस एकता दौड़ में 5 से 14 वर्ष तक के एक हजार बच्चों ने भाग लिया। अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए गए। पुरस्कार के साथ उन्हें धनराशि के चेक भी प्रदान किए गए और उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विक्रम बिधूड़ी भी मौजूद रहे।

एक शाम राष्ट्र के नाम: पीलीभीत में सजेगा राष्ट्र चिंतन का मंच, जाति-धर्म की सीमाओं से परे होगा महामंथन।

परिवहन विशेष न्यूज



पीलीभीत। दीपावली के पावन पर्व के उपरांत सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना और एक आम नागरिक की जिम्मेदारी को सर्वोपरि रखते हुए पीलीभीत जनपद में आगामी दिनों में 'एक शाम राष्ट्र के नाम' कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। हरिओम बाजपेई 'नादान' की परिकल्पना पर आधारित इस अनूठे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग को एक मंच पर लाकर राष्ट्र निर्माण पर गहन विचार-मंथन करना है। यह आयोजन किसी भी राजनीतिक पटल या दलगत भावनाओं से पूरी तरह मुक्त होगा। इसका एकमात्र और पवित्र उद्देश्य राष्ट्र को कैसे अधिक सशक्त बनाया जाएइस इस पर विचार करना है। कार्यक्रम मे सर्वसमावेशी रूपरेखा है, जिसमें छोटे से लेकर बड़े हर नागरिक को जोड़ा जाएगा। इसमें जाति, धर्म और भाषा की दीवारों से परे हटकर केवल और केवल 'राष्ट्र प्रथम' की भावना को प्राथमिकता दी जाएगी। इस राष्ट्रव्यापी विचार-मंथन को धरातल पर उतारने और एक मजबूत कार्ययोजना तैयार करने के लिए जनपद के सभी प्रतिष्ठित और प्रबुद्ध वर्गों को आमंत्रण भेजा जा रहा है। इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व्यापारी वर्ग एवं उद्योग जगत के लोगअधिवक्ता एवं विधि सलाहकारशिक्षा जगत से जुड़े शिक्षक बंधु चिकित्सक एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ साहित्यकार और वाणिज्य से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी

इन सभी गणमान्य नागरिकों के विचारों, सुझावों और अनुभवों को सुनकर आगे की रूपरेखा तय की जाएगी, ताकि प्रशासनिक और सामाजिक तालमेल से पीली भीत से राष्ट्र निर्माण का एक नया संदेश पूरे देश में जा सके। जब सशक्त राष्ट्र सुरक्षित होगा, तभी हम और हमारा समाज सुरक्षित रह पाएगा। हरिओम बाजपेई 'नादान' का कहना है कि सरकार और जिला प्रशासन के साथ-साथ आम नागरिकों को भी राष्ट्र के प्रति अपनी सहयोगी भागीदारी निभानी होगी। आने वाली जन गणना में अपना पूर्ण सहयोग देकर हर नागरिक सशक्त लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। और जब हम सब मिलकर चलेंगे बिना किसी भेद भाव के तभी सही मायनों में राष्ट्र सशक्त बनेगा। आइए, दीपावली के इस उल्लास के बाद पीलीभीत की धरती पर होने वाले इस ऐति हासिक 'एक शाम राष्ट्र के नाम' कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में सहभागी बनें।

ग्रीन फील्ड ई-स्कूल में राष्ट्रीय एकता दिवस पर विद्यार्थियों ने बनाई विशाल मानव श्रृंखला

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का दिया संदेश

परिवहन विशेष न्यूज



गयाजी। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर ग्रीन फील्ड ई-स्कूल, गया के परिसर में राष्ट्रीय एकता दिवस बड़े उत्साह, देशभक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विशाल मानव श्रृंखला बनाई। इसके माध्यम से देश की एकता, अखंडता, आपसी भाईचारे और सामूहिक शक्ति का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना था।

इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक अमय मौर्य ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत विविधता में एकता है। भाषा, धर्म, संस्कृति और परंपराओं में भिन्नता के बावजूद हम सभी एक राष्ट्र के नागरिक हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर प्रेम, सहयोग और भाईचारे के साथ रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल का जीवन दृढ़ इच्छाशक्ति, कुशल नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। प्रत्येक विद्यार्थी को देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

वहीं, विद्यालय के हेड कोऑर्डिनेटर आर.के. वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय एकता केवल एक दिन मनाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे अपने विचारों, व्यवहार और दैनिक जीवन में अपनाना जरूरी है। विद्यार्थियों की ओर से बनाई गई मानव श्रृंखला एकता, विश्वास, सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। उन्होंने विद्यार्थियों से जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर जिम्मेदार नागरिक बनने तथा राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में विशेष उत्साह और अनुशासन देखने को मिला। शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार, ग्रीन फील्ड ई-स्कूल में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस देशभक्ति, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय गौरव की भावना से परिपूर्ण रहा। कार्यक्रम का समापन देश की एकता, अखंडता और सम्मान बनाए रखने में सदैव योगदान देने के संकल्प के साथ हुआ।

लौह पुरुष की चेतावनी, नेताजी का सच

राष्ट्रीय एकता दिवस विशेष

खूंटी। सरदार बल्लभ भाई पटेल की 151 वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विश्व मित्र संघ के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन शहीद भगत सिंह चौक में किया गया। कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विश्व मित्र संघ के अध्यक्ष डॉ दीपक कुमार घोष ने सरदार बल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने 27नवंबर 1948 मे पाकिस्तान को दिए गए पटेल की चेतावनी को अक्षरशः कहा कि > ₹हम कश्मीर और उसके लोगों को नहीं छोड़ेंगे... हम ऐसी धमकियों के आगे झुकने वाले नहीं हैं₹ । मुरहू के समाजसेवी डॉ धर्मेंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि लौह पुरुष की भविष्यवाणी जो बाद में सच हुई। उन्होंने कहा था कि > ₹मिस्टर जिन्ना नहीं समझते कि भूगोल उनके खिलाफ है, कोई उम्मीद नहीं कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान एक राष्ट्र बनकर रहेंगे₹ - यह 1600 किमी की दूरी वाली बात 1971 में बांग्लादेश बनने पर सच साबित हुई । अखिल भारतीय सांस्कृतिक विकास महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तपन घोष ने कहा कि सरदार पटेल का नेताजी से जुड़ाव - कम लोगों को ही पता हो।1945 में रात के अंधेरे में सरदार पटेल ने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की प्रतिबंधित फिल्म को बर्मा (यांगून) से तस्करी कर भारत मंगवाया था। गुजराती इंजीनियर बी.सी. मेहता गनियां बोरियों में रीलें छुपाकर मुंबई लाए और पटेल को दीं। पटेल ने नेहरू, आजाद सहित कांग्रेस हाईकमान को फिल्म दिखाई, जिससे अंग्रेजों का ये प्रचार कि नेताजी जापानी एजेंट हैं, झूठा साबित हुआ। बाद में पटेल ने ही INA के सैनिकों और नेताजी के परिवार की मदद के लिए INA राहत कोष से सहायता की पहल की थी। युवा ध्रुवेन्द्र भास्कर ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर देश के प्रधानमंत्री बने होते तो हमारी ताकत कई गुना होती। वे दुश्मन पड़ोसियों की बंदर घुड़की को सदा के लिए शांत कर दिए देते। कार्यक्रम में गुरु अनुप, जितेन्द्र पांडे, तुलसी प्रजापति, किशोर ठाकुर, बिरसा लोहरा सहित कई गणमान्यजनों ने लौह पुरुष को सच्चा देशभक्त बताया।

आंध्र प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव : माकपा उम्मीदवारों पर तेदेपा गठबंधन के हिंसक हमले

(रिपोर्ट: चलापति जीवीएन, अनुवाद: संजय पराते)





आंध्रप्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों की नामांकन प्रक्रिया सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के समर्थकों द्वारा हिंसा, धमकी और बाधाओं से ग्रस्त रही है। माकपा ने सत्ताधारी पार्टी पर विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने, उनके कागजात छीनने और फाड़ने तथा उम्मीदवारों एवं पार्टी नेताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। इसने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए पुलिस और राज्य निर्वाचन आयोग की भी आलोचना की है।

नगरपालिकाओं के लिए नामांकन 16 से 18 अक्टूबर तक दाखिल किए गए थे तथा मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (एमपीटीसी) और जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (जेडपीटीसी) निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 21 से 23 अक्टूबर तक। मरकापुरम, पलनाडु, कुरनूल, कडप्पा, चित्तूर और तिरुपति सहित कई जिलों से हिंसक घटनाओं की सूचना मिली है।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

विपक्षी युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने हिंसा और रुकावटों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को शिकायतों की जांच करने और यह तय करने का निर्देश दिया कि नामांकन दाखिले का समय बढ़ाया जाए या नहीं। 22 अक्टूबर को आयोग ने चार शहरी स्थानीय निकायों : कडप्पा और तिरुपति निगमों और राजमपेट और म्यदुकुर नगर पालिकाओं के वार्डों में 23 और 24 अक्टूबर को 48 घंटे के लिए नामांकन दाखिले फिर से खोल दिए। उम्मीदवारों की अंतिम सूची 25 अक्टूबर को प्रकाशित की गई।

सभी 100 शहरी स्थानीय निकायों में मतदान अब 1 नवंबर के लिए तय किया गया है और मतगणना 3 नवंबर को होगी। माकपा का कहना है कि नई तारीखों के अलावा स्थिति में बहुत कम बदलाव आया है और हिंसा पहले की तरह जारी है।

उम्मीदवारों पर हमले, कागजात नष्ट किए

मरकापुरम क्षेत्र के पामुरु में माकपा उम्मीदवार सैयद शर्मिला को अपना नामांकन दाखिल करने से रोका गया। उनके कागजात छीन लिए गए और फाड़ दिए गए, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) ने हस्तक्षेप किया और उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय तक पहुंचाया, लेकिन जब वह कतार में इंतजार कर रही थीं, तो टीडीपी समर्थकों ने उन पर फिर से हमला कर दिया और दस्तावेज फाड़ डाले। पुलिस सुरक्षा मिलने के बावजूद वह अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाईं। प्रोद्दुतुर में माकपा उम्मीदवार अंजनेयुलु नाइक पर हमला किया गया, जिससे उनकी कलाई की हड्डी टूट गई। बडवेल में उम्मीदवार मोक्षम्मा के कागजात छीन लिए गए और फाड़ दिए गए, तथा क्रोसुरु और कोसिगी में भी ऐसी ही घटनाएं दर्ज की गईं।

माकपा के आंध्र प्रदेश राज्य सचिव वी श्रीनिवास राव ने पालनाडु जिला सचिवमंडल सदस्य एस अंजनेयुलु नाइक से भेंट की, जिन पर एमपीटीसी चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के समय हमला किया गया था।

कोमारोलु में माकपा के मरकापुरम जिला समिति के सदस्य अवुलैया पर एमपीडीओ कार्यालय के पास लोगों के एक समूह ने तब हमला किया, जब वे पार्टी के उम्मीदवारों की सहायता कर रहे थे। उनके सिर पर गंभीर चोट आई और वे बेहोश हो गए, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें गिद्दलूर सरकारी अस्पताल ले गए। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि यह हमला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुआ, जिन्होंने तुरंत कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

चित्तूर ज़िले के एम बंदापल्ली गाँव में माकपा उम्मीदवार एम कांतम पर हमला किया गया और उनके दस्तावेज़ नष्ट कर दिए गए। तिरुपति ज़िले के ओबुलावरिपल्ली मंडल में उम्मीदवार नागीपोगु पेंचलैया को बार-बार हमलों का सामना करना पड़ा और जब वह नया नामांकन दाखिल करने गए, तो एक पुलिस कांस्टेबल साथ रहने के बावजूद उनके दस्तावेज़ फाड़ दिए गए।

पालनाडु जिले में नरसारावपेटा आरडीओ कार्यालय में जेडपीटीसी नामांकन दाखिल करने का प्रयास करते समय माकपा उम्मीदवार गंजी माला रवि बाबू, पेंड्याला उमा महेश्वर राव, गुंटुपल्ली बालकृष्ण और ईरू कुमारी पर हमला किया गया। राव और बालकृष्ण घायल हो गए। अंततः उम्मीदवारों ने पुलिस की सहायता से अपने नामांकन दाखिल किए।

नकिरीकल्लू में टीडीपी नेता बाजी चौधरी ने रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के भीतर 18 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र छीनकर फाड़ डाले और अधिकारी का मोबाइल फोन भी ले लिया। इस घटना ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप और नामांकन दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

कुरनूल जिले में, माकपा उम्मीदवार मधुसूदन, पार्टी नेता शिवा और अन्य कार्यकर्ताओं पर जिला परिषद कार्यालय में उस समय हमला किया गया, जब वे नामांकन के लिए आवश्यक नो-ड्यूज प्रमाण पत्र मांग रहे थे। कडप्पा जिले में, माकपा उम्मीदवार गांधी सुनील कुमार को ब्रह्ममगारी मठम स्थित नामांकन केंद्र तक बैरिकेड्स और बाधाओं के कारण पहुंचने नहीं दिया गया। विरोध प्रदर्शन और जिला अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद ही उन्हें पर्चा दाखिल करने की अनुमति मिल पाई।

विशाखापत्तनम में यह आरोप लगा कि 14वें वार्ड के वाईएसआरसीपी उम्मीदवार को जबरन और वित्तीय प्रलोभन देकर अपना नामांकन वापस लेने पर विवश किया गया।

माकपा ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की

माकपा राज्य सचिव वी श्रीनिवास राव ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर हार के डर से हिंसा का सहारा लेने और पुलिस पर विपक्षी उम्मीदवारों की रक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।

पार्टी ने यह भी बताया है कि पलनाडु जिले के कुछ क्षेत्रों में पीठासीन अधिकारियों ने माकपा के प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकार करने से इंकार कर दिया, जबकि सत्ताधारी दल के नामांकन स्वीकार किए गए। पार्टी ने पक्षपात के आरोपित अधिकारियों तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पार्टी के नेताओं और उम्मीदवारों पर जातिगत उत्पीड़न तथा हमलों के आरोपितों के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की मांग भी की।

कनिगिरी में, पार्टी ने दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी के नेता स्क्रूटिनी के दौरान विपक्षी उम्मीदवारों को रोककर निर्विरोध जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। राव ने मांग की कि वैध नामांकन स्वीकार किए जाएं और चेतावनी दी कि निष्पक्ष जांच और पर्याप्त सुरक्षा के बिना, चुनाव की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी।

वामपंथी पार्टियों ने हिंसा की निंदा की

23 अक्टूबर को आयोजित एक प्रेस वार्ता में, वामपंथी दलों ने हिंसा की घोर निंदा की। श्रीनिवास राव ने बताया कि तेरह से अधिक जिलों में नामांकन के चरण में ही हिंसा भड़क उठी थी। उन्होंने कहा कि सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रही है, और सत्ताधारी टीडीपी गठबंधन दल इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि उनका एकमात्र उद्देश्य उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकना था। उम्मीदवारों को नामांकन केंद्रों के बाहर रोका गया, और जो लोग अंदर पहुंचे, उनपर भीहमला किया गया, उनके कागजात फाड़ दिए गए, और कुछ मामलों में हथियारों से मारपीट की गई। यह सब यह झूठा भ्रम पैदा करने के लिए किया गया कि सत्ताधारी दलों ने निर्विरोध सीटें जीत ली हैं।

चुनाव की निष्पक्षता सवालों के घेरे में

माकपा ने सत्ताधारी दल, राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के की मांग की है। पार्टी ने निष्पक्ष जांच, हिंसा के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और उम्मीदवारों की रक्षा करने में विफल रहने वाले चुनाव अधिकारियों तथा पुलिस कर्मियों की जवाबदेही तय करने की भी मांग की है।

ये घटनाएं इस बात पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं कि क्या विपक्षी उम्मीदवार स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का आज़ादी से इस्तेमाल कर सकते हैं? राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सही नामांकन स्वीकार किए जाएं, उम्मीदवारों को पूरी सुरक्षा मिले, और यह प्रक्रिया बिना किसी डर-धमकी के हो। सत्ताधारी टीडीपी गठबंधन की पार्टियों को हिंसा और डर-धमकी तुरंत बंद करनी चाहिए, और जनता की मांग है कि सरकार शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करे।

(रिपोर्ट माकपा, आंध्रप्रदेश के नेता हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं।)

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत
https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा विचार

डिजिटल धोखाधड़ी पीड़ितों को मुआवजा एवं बैंकों की जवाबदेही पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणी



पिंकी कुंडू

29 अक्टूबर को साइबर धोखाधड़ी एवं ₹डिजिटल अरेस्ट₹ जैसे मामलों से संबंधित एक महत्वपूर्ण सुनवाई में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी के शिकार व्यक्तियों को उनके नुकसान की भरपाई मिलनी चाहिए। यदि जांच में यह स्थापित होता है कि बैंक या वित्तीय संस्थान की लापरवाही के कारण धनराशि की हानि हुई है, तो उन्हें इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

न्यायालय ने साइबर माध्यम से होने वाले वित्तीय अपराधों में निरंतर वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश योजनाओं, प्रतिरूपण (Impersonation) और अन्य साइबर अपराधों के कारण लोगों की जीवनभर की जमा पूंजी ठगी जा रही है।

प्रकरण का विवरण

In Re: Strengthening Measures to Combat Digital Frauds and Cybercrime

*(आरबीआई द्वारा प्रस्तावित KYC संशोधन निर्देशों एवं डिजिटल धोखाधड़ी की रोकथाम संबंधी उपायों पर कार्यवाही)

पीठ (Bench)

मामले की सुनवाई निम्नलिखित न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई:

- माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत
- माननीय न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची
- माननीय न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना

सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियां

1. पीड़ितों को मुआवजा

न्यायालय ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी के शिकार व्यक्तियों को बिना किसी राहत के नहीं छोड़ा जा सकता। यदि किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा पर्याप्त सावधानी न बरतने के कारण धन की अवैध निकासी हुई है, तो पीड़ित को कम से कम उतनी राशि का मुआवजा मिलना चाहिए जितनी राशि लापरवाही के कारण ठगी गई।

2. वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर कि लेन-देन किसी धोखेबाज द्वारा प्रारंभ किया गया था, बैंक अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते।

यदि निम्नलिखित में कमी पाई जाती है, तो जवाबदेही तय की जा सकती है:

- ग्राहक सत्यापन (Customer Verification)
- उचित परिश्रम (Due Diligence)
- लेन-देन निगरानी (Transaction Monitoring)
- संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग

3. मजबूत धोखाधड़ी-रोधी तंत्र की आवश्यकता

न्यायालय ने निम्नलिखित उपायों की आवश्यकता पर बल दिया:

- सुदृढ़ KYC अनुपालन
- निरंतर लेन-देन निगरानी
- संदिग्ध गतिविधियों की शीघ्र पहचान
- संदिग्ध खातों को तत्काल फ्रीज करना
- बैंकों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों एवं नियामक संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय

4. त्वरित रिपोर्टिंग एवं सूचना साझा करना

पीठ ने निम्नलिखित संस्थाओं के बीच रीयल-टाइम सूचना साझा करने के महत्व को रेखांकित किया:

- बैंक
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
- कानून प्रवर्तन एजेंसियां
- वित्तीय खुफिया इकाइयां (FIUs)
- साइबर अपराध पोर्टल

RBI के प्रस्तावित KYC संशोधन

सर्वोच्च न्यायालय ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने हेतु RBI द्वारा प्रस्तावित KYC संशोधन निर्देशों पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की।

प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य निम्नलिखित को सुदृढ़ करना है:

- ग्राहक उचित परिश्रम (Customer Due Diligence)
- वास्तविक लाभार्थी (Beneficial Ownership) का सत्यापन
- ग्राहकों की सतत निगरानी
- म्यूल (Mule) खातों की पहचान
- संदिग्ध लेन-देन का पता लगाना

इन निर्देशों को नियामकीय समीक्षा के उपरांत चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की संभावना है।

₹डिजिटल अरेस्ट₹ धोखाधड़ी पर न्यायालय की चिंता

सुनवाई के दौरान बढ़ते हुए ₹डिजिटल अरेस्ट₹ मामलों का उल्लेख किया गया, जिनमें साइबर अपराधी स्वयं को निम्नलिखित के रूप में प्रस्तुत करते हैं:

- पुलिस अधिकारी
- CBI अधिकारी
- ED अधिकारी
- न्यायाधीश
- दूरसंचार नियामक अधिकारी

पीड़ितों को वीडियो कॉल के माध्यम से धन शोधन (Money Laundering), मादक पदार्थ तस्करी (Narcotics Trafficking) अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित झूठे आरोपों से डराकर बड़ी रकम ट्रांसफर करवा ली जाती है।

महान्यायवादी (Attorney General) ने न्यायालय को बताया कि डिजिटल अरेस्ट के रिपोर्ट किए गए मामलों में लगभग 50% की कमी आई है, जिसका श्रेय न्यायपालिका, विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी विभागों और जन-जागरूकता अभियानों के समन्वित प्रयासों को दिया गया।

हालांकि, मामलों में कमी आने के बावजूद साइबर धोखाधड़ी अब भी जनता को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा रही है।

साइबर अपराध परिप्रेक्ष्य से महत्व

10. पीड़ित अधिकारों की मान्यता

न्यायालय की टिप्पणी यह स्पष्ट करती है कि धोखाधड़ी के पीड़ितों को केवल नुकसान उठाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि उन्हें सुरक्षा और मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है।



झारखंड के 28 पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री दक्षता मेडल

सारंडा में माओवादियों के सफाए में निभाई अहम भूमिका, आईजी से आरक्षी तक हुए सम्मानित

कार्तिक कुमार परिच्छा स्टेट हेड - झारखंड



रांची, झारखंड पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2026 के गृह मंत्री दक्षता पदक की घोषणा की है। इसमें झारखंड के 28 पुलिस अधिकारियों और जवानों को सम्मान के लिए चुना गया है। इन सभी का चयन स्पेशल ऑपरेशन श्रेणी में उनके बेहतर काम के लिए हुआ है। सम्मान पाने वालों में झारखंड जगुआर के आई जी अनूप बिरथरे डी आई जी इंद्रजीत महथा, डिप्टी कमांडेंट मिथिलेश कुमार डी एस पी ज्ञान रंजन और चंदन कुमार समेत इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ए एस आई, हवलदार और आरक्षी रैंक के जवान शामिल हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, इन पुलिसकर्मियों ने 22 जनवरी से 30 जून 2026 के बीच विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इन पुलिस अधिकारियों और जवानों को झारखंड के माओवादी प्रभावित इलाकों में चलाए गए अभियानों में योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। खासकर पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा क्षेत्र में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से माओवादी संगठन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कई माओवादी मारे गए, जबकि कुछ ने आत्मसमर्पण किया और कई दूसरे राज्यों में चले गए। इन अभियानों में बेहतर रणनीति और पुलिसकर्मियों के आपसी समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गृह मंत्री दक्षता पदक विशेष अभियानों में उत्कृष्ट काम करने वाले पुलिसकर्मियों को दिया जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जवानों तक का चयन होना झारखंड पुलिस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान है।

झारखंड पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2026 के गृह मंत्री दक्षता पदक की घोषणा की है। इसमें झारखंड के 28 पुलिस अधिकारियों और जवानों को सम्मान के लिए चुना गया है। इन सभी का चयन स्पेशल ऑपरेशन श्रेणी में उनके बेहतर काम के लिए हुआ है। सम्मान पाने वालों में झारखंड जगुआर के आई जीज्ञ अनूप बिरथरे डी आई जी इंद्रजीत महथा, डिप्टी कमांडेंट मिथिलेश कुमार डी एस पी ज्ञान रंजन और चंदन कुमार समेत इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ए एस आई, हवलदार और आरक्षी रैंक के जवान शामिल हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, इन पुलिसकर्मियों ने 22 जनवरी से 30 जून 2026 के बीच विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इन पुलिस अधिकारियों और जवानों को झारखंड के माओवादी प्रभावित इलाकों में चलाए गए अभियानों में योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। खासकर पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा क्षेत्र में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से माओवादी संगठन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कई माओवादी मारे गए, जबकि कुछ ने आत्मसमर्पण किया और कई दूसरे राज्यों में चले गए। इन अभियानों में बेहतर रणनीति और पुलिसकर्मियों के आपसी समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गृह मंत्री दक्षता पदक विशेष अभियानों में उत्कृष्ट काम करने वाले पुलिसकर्मियों को दिया जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जवानों तक का चयन होना झारखंड पुलिस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान है।

मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत



वंदे भारत स्लीपर में यात्रियों के साथ ही इसमें काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधा - रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

बनारस में 10 मेमू ट्रेनों का संचलन प्रारंभ

(संतोष कुमार सिंह)

वाराणसी :- मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के करकमलों द्वारा 31 अक्टूबर 2026 शनिवार को बनारस रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, वाराणसी सिटी- राजातालाब के मध्य ट्रेन सेवा एवं प्रयागराज रामबाग-बनारस ट्रेन सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ एवं माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण किया। इस दौरान माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन में बच्चों, यात्रियों एवं रेल कर्मचारियों तथा लोको पायलटों से संवाद किया। उन्होंने रेल कर्मचारियों से सदैव सद्भावपूर्ण व्यवहार करने तथा ट्रेन में स्वच्छता के मानक को बनाये रखने का आह्वान किया और लोको पायलटों का उत्साहवर्धन किया।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार बल्लभ भाई पटेल जी जयंती पर उनको नमन करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में देश एवं भारतीय रेल आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेल देश को उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम तक सम्पूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरो कर स्वतंत्रता सेनानियों एवं राष्ट्र नायकों के सपनों को साकार कर रही रही है उन्होंने कहा कि आम भारतीय की सवारी भारतीय रेल को आधुनिक स्वरूप दिया है। प्रदेश में पहले आधा मीटर गेज आधा ब्रॉड गेज होता था आज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी लाइनें ब्रॉड गेज की है और विद्युतीकृत हैं उन्होंने कहा की काशी से दिल्ली जाने में 13 से 14 घंटे पहले लगते थे आज वंदे भारत स्लीपर से यह दूरी 8 से 9 घंटे में पूरी होगी।

पहली वंदे भारत नई दिल्ली से वाराणसी के लिए चलाई गयी थी और उसमें चेयर कार की सुविधा है और आज से चली जा रही वंदे भारत स्लीपर से आपकी यात्रा काफी सुखद होगी। यात्री काशी से रात्रि में चलकर सुबह दिल्ली तथा दिल्ली से रात्रि में चलकर सुबह काशी पहुचेंगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देश की आध्यात्मिक राजधानी को देश की राजधानी से जोड़ेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका है वाराणसी सिटी से राजातालाब तक यात्रियों की सुविधा के लिए मेमू ट्रेन का संचालन किया जा रहा है 95 रूपये में इससे महीने भर में यात्रा होगी। आज से बनारस से प्रयागराज के लिए मेमू ट्रेन का शुभारम्भ किया जा रहा है इसका महीने भर का किराया मात्र 220 रुपया है यह काफी आकर्षक और सुविधाजनक है ।अधिवक्ताओं, व्यावसायियों, किसानों, छात्रों, महिलाओं के लिए यह एक अच्छी सुविधा है भारतीय रेल आज तेजी से मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ा है पहले अनारक्षित समपार भारतीय रेल की चुनौती थी, दुर्घटनाओं में सैकड़ों की मात्रा में जनहानि होती थी। आज रोड ओवर ब्रिज या अंडर पास की सुविधा है यह रेलवे का जनता के प्रति रेलवे के संवेदनशीलता का उदाहरण है। प्रदेश वासियों के लिए गौरव की बात है की फ्रेट कॉरिडोर का एक हजार किलोमीटर से अधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश में है इसके लिए अलग लाइन बनाई गयी है, और माल जल्दी और सुरक्षित पहुंचता है। दिल्ली से काशी के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर बनने से साढ़े तीन घंटे में यह दूरी तय होगी।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी, वाराणसी, बनारस सहित प्रदेश में 157 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है, फसाड में स्थानीय संस्कृति दिखाई पड़ रही है। स्टेशनों पर स्वच्छता काफी बढ़ी है आज रेलवे पटरियां, रेलवे स्टेशन एवं ट्रेनें काफी स्वच्छ है इन नयी ट्रेन सेवाओं के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज बनारस से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के साथ दस मेमू ट्रेनों का संचलन प्रारंभ हो रहा है। वाराणसी सिटी- राजातालाब के मध्य आठ मेमू ट्रेन अपने यात्रा मार्ग में वाराणसी, बनारस, भुलनपुर, हरदत्तपुर स्टेशनों पर रुकेगी। इस गाड़ी से वाराणसी सिटी से राजातालाब तक एमएसटी का किराया 95 रुपया है दो मेमू ट्रेन जो की बनारस से प्रयागराज को जोड़ेगी जिससे छात्रों, किसानों, व्यावसायियों को काफी सुविधा होगी। यह मेमू सेवा अपने मार्ग में राजातालाब, माधोसिंह, ज्ञानपुर रोड, हंडिया खास और झूसी स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन से छात्रों के लिए बनारस से प्रयागराज तक का एक महीने का किराया 220 रुपया है।

श्री वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत स्लीपर में यात्रियों के साथ साथ इसमें काम करने वाले कर्मचारियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। रेलवे पर प्रधानमंत्री जी की विशेष दृष्टि रहती है इस ट्रेन में मध्य एवं उपर के बर्थों पर चढ़ने के लिए नये तरीके की सीढ़ियाँ लगायी गयी है यह ट्रेन न केवल वाराणसी बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए बड़ी सौगात होगी। यह गाड़ी का समयसारणी इस प्रकार का है कि रात में वाराणसी से चलकर सुबह दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से रात्रि में चलकर सुबह वाराणसी पहुंचे। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर जो कोलकाता से गुवाहाटी के बीच चलती है वह जनता में काफी लोकप्रिय हुयी है आलोचकों ने भी काफी इस गाड़ी की काफी प्रशंसा की है।

रेल मंत्री ने कहा कि सरकार ने बुलेट ट्रेन के नार्थ कॉरिडोर की स्वीकृति प्रदान की है यह कॉरिडोर दिल्ली से आगरा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, पटना होते हुए गुवाहाटी जाएगी। इस परियोजना के पूरा होने पर समय की बचत काफी होगी। दिल्ली से वाराणसी की दूरी साढ़े तीन घंटे में पूरी होगी यह बुलेट परियोजना पूर्णतः स्वदेशी होगी पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेल में अभूतपूर्व बदलाव हुये हैं इसका प्रमुख कारण रेलवे के लिये पर्याप्त धनराशि का आवंटन है। उत्तर प्रदेश में रेलवे का इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार तेजी से करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में 20,012 करोड़ रूपये आवंटित किये गये है जो यूपीए सरकार (2009-14) द्वारा आवंटित धनराशि की तुलना में 18 गुणा अधिक है।

प्रयागराज रामबाग स्टेशन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी नई दिल्ली के मध्य वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, प्रयागराज रामबाग-बनारस ट्रेन सहित अन्य ट्रेन सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। विधायक वाराणसी कैंट सौरभ श्रीवास्तव ने नई गाड़ियों के संचलन हेतु प्रधानमंत्री रेल मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया।

इस अवसर पर बनारस रेलवे स्टेशन पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, मंत्री रविन्द्र जायसवाल, मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र "दयालु", मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, महापौर अशोक तिवारी, विधायक डॉ.नीलकंठ तिवारी, विधायक सुनील पटेल, विधायक अवधेश सिंह, सदस्य विधान परिषद धर्मेन्द्र सिंह, सदस्य विधान परिषद श्याम नारायण सिंह, सदस्य विधान परिषद अन्नपूर्णा सिंह तथा प्रयागराज रामबाग स्टेशन पर आयोजित समारोह में औद्योगिक विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नन्द गोपाल गुप्ता नंदी तथा विधायक प्रयागराज उत्तर हर्षवर्धन बाजपेयी उपस्थित थे।

पूर्व तट रेलवे मुख्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओडिशा



भुवनेश्वर : भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर पूर्व तट रेलवे (ECoR) की ओर से उसके मुख्यालय रेल सदन, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री परमेश्वर फुंकवाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के साथ उत्साहपूर्ण एकता के लिए दौड़' (Run for Unity) रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री फुंकवाल ने पूर्व तट रेलवे के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। इस शपथ के माध्यम से देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने तथा सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय एकता के आदर्शों को कायम रखने के प्रति सभी ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

शपथ ग्रहण समारोह के बाद महाप्रबंधक ने रेल सदन के सामने से 'एकता के लिए दौड़' रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान, खिलाड़ी तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन ने एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को प्रदर्शित किया।

इस अवसर पर पूर्व तट रेलवे के सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को मजबूत बनाने के प्रति अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम का समन्वय पूर्व तट रेलवे के कार्मिक विभाग द्वारा किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन देश को एकजुट करने में सरदार वल्लभभाई पटेल के अमूल्य योगदान की याद दिलाता है। साथ ही यह भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने में प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी को भी मजबूत करता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023